www.cgfrontline.com

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

■ वर्ष: 01 ■ अंक: 71 ■ जशपुर, 30 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) ■ पृष्ठ: 08 ■ मूल्य: 01 रूपये

स्मृति इरानी के दौरे ने चढ़ाया सियासी पारा, बीजेपी ने शुरू की मिशन 2028 की तैयारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने मिशन 2028 की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रदेश प्रभारी बनने के बाद स्मृति इरानी के पहले दो दिवसीय रायपुर दौरे ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। दो दिन में कोर ग्रुप से लेकर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पूर्व पदाधिकारियों तक लगभग 12 अलग-अलग श्रेणियों की मैराथन बंद कमरों में बैठकें हुईं। सार्वजनिक तौर पर बीजेपी इसे परिचय सत्र और संगठनात्मक समन्वय बता रही है, लेकिन अंदरखाने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और काम में सुधार के सख्त निर्देशों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

प्रदेश अध्यक्ष ने बताया

प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के मुताबिक, "स्मृति जी ने सभी वर्गों से परिचय लिया और उनके क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बूथ स्तर तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है।"

मंत्रियों को मिला सुधार का संदेश

रायपुर में बीजेपी प्रभारी स्मृति इरानी की मंत्रियों के साथ हुई बैठक की सबसे

ज्यादा चर्चा है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम से जब बैठक के बारे में पूछा गया तो बोले - "घर की बात है, घर में रहने दो।" मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने माना कामकाज में कमियां दूर करने और सुधार के निर्देश मिले हैं। मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा की स्मृति जी के अनुभव से संगठन में कसावट आएगी। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा बीजेपी में 5 साल संगठन का काम चलता है, अलग से तैयारी की जरूरत नहीं। मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा पार्टी गतिविधियों की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।

कांग्रेस ने लगाया कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप

कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने हमला बोलते हुए कहा, "स्मृति इरानी ने सिर्फ बड़े नेताओं से बैठक की, जिला अध्यक्षों और जमीनी कार्यकर्ताओं को कार्यालय तक आने से रोका गया। इस तरह की कार्यशैली से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। वो दो-चार बार और आईं तो कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे।"

क्या कह रहे हैं विश्लेषक

वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा के मुताबिक, "स्मृति इरानी आक्रामक और अनुभवी नेता हैं। अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद उनकी पहचान मजबूत हुई है। उन्होंने बैठकों में भाषणबाजी और टैगलाइन से परहेज कर परिपक्वता दिखाई। बीजेपी की बैठकों के एजेंडे कभी सार्वजनिक नहीं होते। कुछ समय से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की शिकायतें थीं, ऐसे में उनका अलग-अलग स्तरों पर संवाद संगठन को सक्रिय करने की कोशिश है।"

2018 में बीजेपी को कार्यकर्ताओं की निराशा और एंटी इनकंबेंसी का सामना करना पड़ा था। विश्लेषकों का मानना है कि 2028 से पहले संगठन उसी गलती को दोहराना नहीं चाहता। अब सवाल यही है कि क्या इस फीडबैक के बाद मंत्रियों के काम में सुधार दिखेगा? क्या कार्यकर्ताओं की सुनवाई होगी? घर की बात घर में कितनी देर रहेगी, यह आने वाले महीनों में सरकार के कामकाज और संगठन की सक्रियता से पता चलेगा।

रायपुर पुलिस हुई हाईटेक, अब फेसबुक-इंस्टाग्राम पर सुन रही शिकायतें, हर रविवार लाईव जवाब

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। पुलिस अब थाने से निकलकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई है। अब राजधानी के लोगों को शिकायत के लिए थाने के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सीधे पुलिस तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और पुलिस भी तुरंत एक्शन ले रही है। फरवरी 2026 से रायपुर कमिश्नरेट ने सोशल मीडिया पर बड़ा अभियान शुरू किया है, जिसका रिजल्ट चौंकाने वाला है।

हर महीने 14 करोड़ से ज्यादा व्यूज

रायपुर पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रिकॉर्ड तोड़ रिस्पॉन्स मिल रहा है। फेसबुक पर - हर महीने 6.77 करोड़ व्यूज, जो पिछले साल से 124% ज्यादा है। फॉलोअर्स 35% बढ़कर 1.65 लाख हो गए। इंस्टाग्राम पर - हर महीने 8.84 करोड़ व्यूज, पिछले साल से 291% की बढ़ोतरी। फॉलोअर्स 37% बढ़कर 1.25 लाख। इंगेजमेंट भी फेसबुक पर 63% और इंस्टा पर 135% बढ़ा है।

हर रविवार पुलिस का लाईव दरबार

'फेसबुक 2.0' कार्यक्रम के तहत हर रविवार पुलिस के बड़े अफसर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाईव आते हैं। लोग लाइव में ही अपनी समस्या बताते हैं, सवाल पूछते हैं और अफसर वहीं पर जवाब देकर समाधान करते हैं।

2 मिनट के वीडियो से क्राइम की पाठशाला

'सुरक्षा की बात अपनों के साथ' अभियान के तहत पुलिस अफसर 2-3 मिनट के छोटे-छोटे वीडियो बनाकर लोगों को साइबर ठगी, महिला-बच्चों से जुड़े अपराध और ट्रैफिक नियमों के बारे में बता रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा शॉर्ट फिल्में बनाई गई हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के साथ-साथ सिनेमाघरों में भी दिखाया गया।साइबर अपराध रोकने के लिए 'साइबर जागृति' और 'साइबर संकल्प' के 9 ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल भी तैयार किए गए हैं।

ट्रैफिक सुधारने जनता से आइडिया

'ट्रैफिक हैकाथॉन 2026' में "हमारा शहर, हमारी सड़कें, हमारे सुझाव" थीम पर आम लोगों, छात्रों, इंजीनियरों और गृहिणियों से सुझाव मांगे गए।

अच्छे सुझावों को लागू किया गया और मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर अर्चना झा ने बताया, "सोशल मीडिया से मिली शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद बढ़ा है।"

पूर्व मुख्यमंत्री ने दुर्ग की मतदाता सूची में लगाया गड़बड़ी का आरोप, बोले- बिना परिसीमन आरक्षण कैसे बदला?

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

दुर्ग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया है। गुरुवार को भिलाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले जारी मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम एक वार्ड से दूसरे वार्ड में चले गए हैं और बिना परिसीमन के ही सैकड़ों मतदाताओं के बूथ बदल दिए गए हैं। इस साल के अंत में दुर्ग जिले में भिलाई नगर निगम, भिलाई-चरोदा निगम, रिसाली निगम और जामुल नगर पालिका के चुनाव होने हैं। इसी को लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया था। बघेल ने कहा, "जो सूची हमारे जिला अध्यक्षों को सौंपी गई है, उसमें भारी गड़बड़ी है। सभी निकायों में मतदाताओं के वार्ड-बूथ बदल गए हैं। इससे चुनाव में प्रत्याशियों के प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ेगा।"

भूपेश बघेल की 3 बड़ी मांगें

दावा-आपत्ति की तारीख बढ़ाई जाए: मतदाता सूची जारी होने के दूसरे दिन जिला अध्यक्षों को मिली और दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। इतने कम समय में आपत्ति दर्ज कराना मुश्किल है। वार्डों में बीएलओ बैठ ही नहीं रहे हैं, जिससे लोग आपत्ति नहीं कर पा रहे हैं।

मतदाता सूची फिर से अपडेट हो: बिना परिसीमन के वार्ड के आरक्षण कैसे बदल गए? सैकड़ों मतदाताओं के वार्ड बदलने से चुनावी नतीजे प्रभावित होंगे, इसलिए पूरी सूची को फिर से ठीक किया जाए।

दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई: बीएलओ वार्डों में बैठने के बजाय नगर निगम दफ्तर में बैठकर सूची सुधार रहे हैं, यही साबित करता है कि गड़बड़ी हुई है। इसमें शामिल सरकारी और गैर-सरकारी लोगों पर कार्रवाई हो।

बघेल ने कहा, "पहली बात है कि आपत्ति करने का समय बदलना चाहिए, दूसरी बात परिसीमन हुआ नहीं तो वार्ड के आरक्षण कैसे बदल गए?"

ईओडब्ल्यू-एसीबी से 12 पुलिसकर्मियों की छुट्टी, गृह विभाग को लौटाई सेवाएं

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू)

और एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने दोनों एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात 12 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके मूल विभाग गृह विभाग को वापस कर दी हैं। इस संबंध में जीएडी ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं।

पहले आदेश के अनुसार 5 निरीक्षकों वीरेंद्र चंद्रा, शरद चंद्रा, बृजेश कुशवाहा, संतराम सोनी, उमेंद्र टंडन को वापस भेजा गया है। दूसरे आदेश में कुल 7 नाम हैं, जिनमें निरीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर तक के कर्मी शामिल हैं। निरीक्षक पौरुष पुर्रे, निरीक्षक सौरभ द्विवेदी, उप निरीक्षक जितेंद्र नंदे, सहायक उप निरीक्षक निर्भय लाल ध्रुव, आरक्षक अभिषेक कुमार, आरक्षक रितेश दीवान, आरक्षक सोहन ध्रुव, विभागीय आदेश में इस फेरबदल के पीछे के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अचानक 12 लोगों को एक साथ हटाए जाने से ईओडब्ल्यू-एसीबी में चल रहे कई संवेदनशील मामलों की जांच पर असर पड़ने की चर्चा है। सभी की सेवाएं तत्काल प्रभाव से गृह विभाग को लौटा दी गई हैं।

सरगुजा में चक्रवात अर्नब का कहर, दो दिन में 27 मिमी बारिश

धान की फसल बर्बाद, आज भी सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती सिस्टम 'अर्नब' का असर उत्तर छत्तीसगढ़ में तेज हो गया है। सरगुजा

संभाग में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर रिमझिम बारिश के साथ तेज हवा चल रही है। अंबिकापुर में अब तक 27 मिमी बारिश दर्ज की गई है। बारिश और तेज हवा से मौसम में ठंडक काफी बढ़ गई है, जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है।

अलर्ट के बाद आज भी स्कूल बंद

मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम अर्नब के प्रभाव से 30 अक्टूबर को तेज आंधी, गरज-चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसे देखते हुए कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर ने आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार को भी एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। इससे पहले भी बारिश के कारण स्कूलों में छुट्टी दी गई थी। यानी सरगुजा में लगातार दूसरे दिन भी स्कूल बंद रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने बाबा कार्तिक उरांव की जन्मशताब्दी पर किया आदमकद प्रतिमा का अनावरण

शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम अब अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होगा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। बंगाल की खाड़ी में बने अर्नब चक्रवात के कारण मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का सरगुजा दौरा स्थगित हो गया, लेकिन बाबा कार्तिक उरांव जन्मशताब्दी समारोह का उत्साह कम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को रायपुर स्थित सिविल लाइन मुख्यमंत्री निवास से वर्चुअल माध्यम से अंबिकापुर में आयोजित समारोह में शामिल होकर जनजातीय समाज के महान जननायक, प्रख्यात अभियंता एवं पूर्व सांसद बाबा कार्तिक उरांव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इसके पहले शहर में बरसते पानी में महारैली निकली, जिसमें परंपरागत वेशभूषा में लोग शामिल हुए। सांसद सरगुजा चिंतामणि महराज सहित कई जनप्रतिनिधि भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए 3 बड़ी घोषणाएं की। सबसे बड़ी घोषणा शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय डिगमा का नाम बदलकर अभियंता बाबा कार्तिक उरांव छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अंबिकापुर करने की है। साथ ही सीतापुर में सोनतराई से सूर तक 3.82 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क का भूमिपूजन किया, जिस पर 28 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। इसके अलावा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित महिला एनजीओ मेस, उदयपुर में 12 अराजपत्रित अधिकारी आवास, 12 प्रधान आरक्षक-आरक्षक आवास और थाना सीतापुर में 12 आवासीय भवनों का लोकार्पण किया।

बाबा कार्तिक उरांव का जीवन स्वाभिमान और उत्थान के लिए समर्पित रहा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव केवल जनजातीय समाज के नेता नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी विचारक, उच्च शिक्षित अभियंता और समाज के अधिकारों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने उस समय इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और विदेश में भी उच्च अध्ययन किया, जब जनजातीय समाज के लिए शिक्षा के अवसर अत्यंत सीमित थे। उनकी यह उपलब्धि पूरे समाज के लिए गौरव और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव ने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम नहीं माना, बल्कि इसे समाज में परिवर्तन लाने का सबसे सशक्त साधन बनाया। उनका विश्वास था कि शिक्षा,

संगठन और जागरूकता के माध्यम से ही समाज अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए विकास की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने समाज को अपनी परंपराओं, संस्कृति और मूल पहचान के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

सांसद के रूप में उन्होंने लोकसभा में जनजातीय समाज की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। धर्मांतरण के बाद जनजातीय आरक्षण एवं अन्य संवैधानिक सुविधाओं के लाभ से जुड़े विषयों को भी उन्होंने प्रमुखता से उठाया था। उनका मानना था कि जनजातीय समाज की समृद्ध परंपराएं और रीति-रिवाज ही उसकी मूल पहचान हैं, इनका संरक्षण करते हुए शिक्षा और तकनीक से जोड़ना आवश्यक है।

इंजीनियरिंग कॉलेज का नामकरण नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पूर्व इस प्रतिमा की स्थापना के लिए भूमिपूजन किया गया था और आज यह संकल्प साकार हो रहा है। इसके लिए महापौर मंजूषा भगत, जनप्रतिनिधियों और नगर निगम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाबा कार्तिक उरांव स्वयं प्रतिभाशाली अभियंता थे, इसलिए उनके नाम पर इंजीनियरिंग संस्थान का नामकरण विशेष महत्व रखता है। यह संस्थान न केवल तकनीकी शिक्षा का केंद्र बनेगा, बल्कि यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उनके संघर्ष और समर्पण से प्रेरणा भी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय महापुरुषों की गौरवशाली विरासत को चिरस्थायी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक दिन पूर्व ही पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय काका लरंग साय की प्रतिमा का उनके गृहग्राम चिरई-जसवंतपुर में अनावरण किया गया था। ऐसे प्रयास समाज में अपनी विरासत के प्रति सम्मान और आत्मगौरव को मजबूत करते हैं।

सीतापुर में फोरलेन से विकास को नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के विकास का आधार होता है। सीतापुर सरगुजा अंचल का महत्वपूर्ण व्यापारिक और आवागमन केंद्र है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक शासकीय कार्यों, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यहां आते हैं। 3.82 किलोमीटर फोरलेन बनने से पूरे शहरी क्षेत्र में यातायात सुगम और सुरक्षित होगा, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

पुलिस आवासों के लोकार्पण पर उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका है। बेहतर आवासीय सुविधाओं से जवानों और उनके परिवारों को सुविधाजनक वातावरण मिलेगा और वे और अधिक मनोबल के साथ कर्तव्य निभा सकेंगे।

नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता से बस्तर में शांति का नया युग

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के तीन वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, गृहमंत्री अमित शाह के दृढ़ संकल्प और सुरक्षाबलों के साहस से नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। बस्तर के जनजातीय भाई-बहनों को चार दशकों तक नक्सलवाद की चुनौती झेलनी पड़ी, जहां सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा जैसी सुविधाएं पहुंचाना कठिन था। अब उन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि बस्तर के प्रत्येक गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचें।

छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत यहां के लोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत यहां के सरल, मेहनती और प्रतिभाशाली लोग हैं। 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' केवल कहावत नहीं, बल्कि यहां के लोगों के स्वभाव की अभिव्यक्ति है। विकसित भारत 2047 के संकल्प में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कार्यक्रम में जनजातीय विकास मंत्री रामविचार नेताम, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, सांसद चिंतामणि महाराज ने भी बाबा कार्तिक उरांव के योगदान को याद किया। सांसद महाराज ने इंजीनियरिंग कॉलेज के नामकरण और फोरलेन की सौगात के लिए सीएम का आभार जताया।

कलाकेंद्र में आयोजित कार्यक्रम में सामरी विधायक उद्धेश्वरी पैकरा, महापौर मंजूषा भगत, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह, संभागायुक्त नरेंद्र कुमार दुग्गा, आईजी दीपक कुमार झा, कलेक्टर अजीत वसंत, एसएसपी राजेश अग्रवाल, उरांव समाज अध्यक्ष आजाद भगत सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और समाज के लोग मौजूद रहे।

चक्रवाती तूफान की बारिश ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी

खेतों में खड़ी फसल से लेकर खलिहानों में रखे धान तक पर मंडराया नुकसान का खतरा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। चक्रवाती तूफान के प्रभाव से मौसम में आए अचानक बदलाव ने कोयलांचल सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बुधवार दोपहर से शुरू हुई बारिश का सिलसिला गुरुवार को भी लगातार जारी रहने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में लहलहा रही धान की फसल से लेकर कटाई के बाद खलिहानों में रखे धान तक पर बारिश की मार पड़ रही है। वहीं सब्जी उत्पादन के लिए पहचाने जाने वाले सिलफिली और आसपास के गांवों में भी मौसम के बदले मिजाज से सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचने की खबर है। अचानक बदले मौसम ने किसानों की महीनों की मेहनत और लागत पर संकट खड़ा कर दिया है। यूं तो खेती-किसानी पूरी तरह मौसम पर निर्भर रहती है। किसान पूरे सीजन खेतों में पसीना बहाकर फसल तैयार करते हैं और जब उपज घर लाने का समय नजदीक आता है, तब मौसम की प्रतिकूलता उनकी मेहनत पर भारी पड़ने लगती है। कोयलांचल क्षेत्र में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश ने एक बार फिर किसानों के सामने इसी तरह की चुनौती खड़ी कर दी है। बुधवार दोपहर से आसमान में छाए बादलों और शुरू हुई बारिश ने ग्रामीण इलाकों का सामान्य जनजीवन प्रभावित किया। गुरुवार को भी बारिश जारी रहने से किसानों की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती नजर आईं। धान की फसल को लेकर किसानों की चिंता स्वाभाविक है। खेतों में खड़ी फसल को सुरक्षित रखने के साथ कटाई के बाद उपज को सूखाकर भंडारित करना भी जरूरी होता है। ऐसे समय में लगातार बारिश होने से खेतों में मौजूद फसल और खुले में रखी उपज दोनों के प्रभावित होने की आशंका बढ़ जाती है। किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे मौसम की इस अनिश्चितता के बीच अपनी मेहनत से तैयार उपज को आखिर किस तरह सुरक्षित रखें। धान की खेती करने वाले किसानों के लिए केवल खेतों में खड़ी फसल ही चिंता का कारण नहीं है, बल्कि खलिहानों में रखे धान की सुरक्षा भी बड़ी समस्या बन गई है। कटाई के बाद खुले स्थानों पर रखी गई फसल बारिश के पानी से भीगने पर उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। धान को पर्याप्त रूप से सुखाने और सुरक्षित रखने में परेशानी आने से किसानों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। यदि धान लंबे समय तक नमी की चपेट में रहता है, तो उसके खराब होने, रंग और गुणवत्ता प्रभावित होने तथा भंडारण के दौरान परेशानी बढ़ने का खतरा रहता है। इससे किसानों को उपज के उचित मूल्य को लेकर भी चिंता हो सकती है। हालांकि, क्षेत्र में धान की फसल को हुए वास्तविक नुकसान का आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार बारिश ने किसानों की आशंकाएं जरूर बढ़ा दी हैं। खेतों में खड़ी धान की फसल के लिए लगातार बारिश और नमी की स्थिति नुकसानदायक साबित हो सकती है। खेतों में पानी जमा होने की स्थिति बनने पर फसल प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही बारिश के कारण कटाई और उपज को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में देरी हो सकती है। मौसम की मार से उत्पादन प्रभावित होने की आशंका किसानों को भविष्य की आमदनी और घरेलू जरूरतों को लेकर भी परेशान कर रही है।

सिलफिली की सब्जी खेती पर भी मौसम का असर

ग्राम पंचायत सिलफिली और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी की खेती अनेक किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। यहां उत्पादित सब्जियां स्थानीय बाजारों और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचती हैं। लेकिन चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बदले मौसम और लगातार बारिश ने सब्जी उत्पादकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्षेत्र में सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। सब्जी की खेती में अत्यधिक नमी और खेतों में पानी जमा होने से पौधों की जड़ों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कुछ फसलों में रोग लगने की आशंका बढ़ जाती है, जबकि फूल और फल आने की अवस्था में प्रतिकूल मौसम उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। लगातार बारिश के कारण खेतों में काम करना, फसलों की देखभाल करना और तैयार सब्जियों को बाजार तक पहुंचाना भी मुश्किल हो सकता है। सब्जी उत्पादकों के सामने एक और चुनौती यह है कि सब्जियां जल्दी खराब होने वाली उपज हैं। यदि बारिश के कारण उत्पादन या बाजार तक पहुंच प्रभावित होती है, तो इसका सीधा असर किसानों की रोजाना होने वाली आमदनी पर पड़ सकता है। फसल तैयार होने के बाद मौसम बिगड़ जाए, तो किसानों के सामने नुकसान की भरपाई की बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। लगातार बारिश के बीच किसानों की नजर अब मौसम साफ होने और फसलों की वास्तविक स्थिति सामने आने पर टिकी है। खेतों में खड़ी फसल, खलिहानों में रखे धान और सब्जी की खेती को हुए नुकसान का आकलन होने के बाद ही प्रभावित किसानों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

निरीक्षक ढाल सिंह साहू बनाए गए जयनगर थाना प्रभारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने जिले के आठ निरीक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अतिरिक्त दो उपनिरीक्षक, आठ सहायक उपनिरीक्षक सहित अलग अलग थानों में पदस्थ पचपन आरक्षकों का तबादला कर उन्हें नए थाना चौकियों में पदस्थापित किया है।गुरुवार को पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में निरीक्षक रंजीत प्रताप सिंह रक्षित केंद्र से शिकायत शाखा प्रभारी पुलिस कार्यालय, निरीक्षक रमेश पटेल रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी रामानुजनगर, निरीक्षक नंद किशोर गौतम रक्षित केंद्र से रीडर टू एसपी कार्यालय, निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी रमकोला, निरीक्षक मिलन सिंह रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी चांदनी, निरीक्षक ढाल सिंह साहू रक्षित केंद्र से थाना प्रभारी जयनगर, निरीक्षक रूपेश कुंतल एक्का रक्षित केंद्र से प्रभारी साईबर सेल, निरीक्षक जावेद मियादाद को डीसीबी/डीसीआरबी/कंट्रोल रूम का प्रभारी बनाया गया है।उपनिरीक्षक अमित कुमार गुप्ता थाना प्रभारी जयनगर से चौकी प्रभारी बसदेई, उपनिरीक्षक हीरालाल साहू को थाना प्रभारी रमकोला से थाना सूरजपुर, अरुण गुप्ता को साईबर सेल से चौकी प्रभारी करंजी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार एएसआई अमरेश सिंह रक्षित केंद्र से साईबर सेल, वरुण तिवारी को जयनगर, पास्कल लकड़ा को रक्षित केंद्र से थाना रामानुजनगर, बबिता यादव रक्षित केंद्र से थाना बिश्रामपुर, राकेश यादव को थाना प्रतापपुर, हरिशंकर तिवारी को बिश्रामपुर से थाना चंदौरा, सुनील भारती को चंदौरा से भटगांव पदस्थ किया गया है। आदेश में आधा दर्जन प्रधान आरक्षक के अलावा आरक्षकों को भी नई पोस्टिंग दी गई है।

कोल इंडिया कर्मचारियों की एचआरए की दरों में हुई बढ़ोतरी

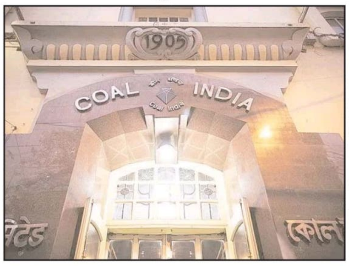

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन
बिश्रामपुर। कोल इंडिया के कर्मचारियों के लिए मकान किराया भत्ते को लेकर बड़ी राहत की खबर है। कोल इंडिया प्रबंधन ने एचआरए की दरों में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। संशोधित दरों के अनुसार अब एक्स श्रेणी के शहरों में मूल वेतन का 27 प्रतिशत, वाई श्रेणी में 18 प्रतिशत और जेड श्रेणी के शहरों में 9 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलेगा। नई दरें 1 सितंबर 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।

इस संबंध में कोल इंडिया के मानव संसाधन विभाग ने 22 अक्टूबर को कार्यालय आदेश जारी किया है। इस निर्णय से कंपनी में कार्यरत उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें नियमानुसार मकान किराया भत्ते की पात्रता है। ज्ञात हो कि एचआरए कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसका उद्देश्य आवास संबंधी खर्चों में आर्थिक सहायता देना है। शहरों की श्रेणी के आधार पर भत्ते की दरें निर्धारित की गई हैं। नई व्यवस्था के तहत एक्स श्रेणी के शहरों में सबसे अधिक 27 प्रतिशत, वाई श्रेणी में 18 प्रतिशत और जेड श्रेणी के शहरों में 9 प्रतिशत की दर से भत्ता देय होगा।

इस बढ़ोतरी से पात्र कर्मचारियों की मासिक वेतन गणना में बदलाव होगा। हालांकि वास्तविक लाभ कर्मचारी के मूल वेतन, पदस्थापना स्थल की श्रेणी और लागू सेवा नियमों के आधार पर निर्धारित होगा। ज्ञात हो कि कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों और कोयला क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए इस आदेश का महत्व है। नई दरें प्रभावी तिथि से लागू होने के कारण कर्मचारी अपने वेतन विवरण में संशोधित एचआरए और नियमानुसार देय अंतर की जानकारी का इंतजार करेंगे। आदेश के क्रियान्वयन के दौरान संबंधित कार्यालयों द्वारा पात्रता और भुगतान संबंधी नियमों के अनुरूप वेतन निर्धारण किया जाएगा। एचआरए दरों में इस संशोधन से कर्मचारियों को आवासीय खर्चों के मद में अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। अब कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि संशोधित दरों के अनुसार भुगतान और बकाया अंतर का समायोजन किस प्रकार किया जाता है।

मखाना की खेती से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहीं धमतरी की महिलाएं

धमतरी, छ.ग. फ्रंटलाइन। धमतरी जिले में कृषि विविधीकरण और ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की दिशा में मखाना की खेती नई संभावनाएं पैदा कर रही है। तालाबों में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने की पहल अब परिणाम देने लगी है। इसी कड़ी में ग्राम छाती और डांडेसरा में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 29 एकड़ क्षेत्र में उत्पादित मखाना का संग्रहण शुरू हो गया है। साथ ही, महिलाओं को मखाना के संग्रहण और संग्रहण-पश्चात प्रबंधन की वैज्ञानिक तकनीकों का प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। इससे उपज की गुणवत्ता, प्रसंस्करण और बाजार में बेहतर मूल्य मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।

केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना के तहत वर्ष 2025-26 में धमतरी जिले को तालाबों में मखाना की खेती के लिए 165 एकड़ का लक्ष्य दिया गया था। इसके मुकाबले जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में 105 एकड़ क्षेत्र में मखाना की खेती शुरू की गई। ग्राम राखी, छाती, डांडेसरा और पीपरछेड़ी के साथ नगरी विकासखंड के ग्राम सांकरा में भी इस फसल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

ग्राम छाती और डांडेसरा में शैलपुत्री स्व-सहायता समूह तथा नई किरण स्व-सहायता समूह की महिलाओं के लिए 26 अक्टूबर को मखाना संग्रहण की शुरुआत और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ग्राम छाती-सेनचुवा की सरपंच श्रीमती दानेश्वरी साहू, श्री जितेन्द्र कुमार साहू, पंचगण, कृषि विज्ञान केंद्र की विशेषज्ञ श्रीमती दीपिका चंद्रवंशी, उप संचालक उद्यानिकी श्रीमती पूजा कश्यप साहू, उद्यान विकास अधिकारी श्री राहुल साहू और ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्री नर्मदा प्रसाद भारती उपस्थित रहे।

उप संचालक उद्यानिकी श्रीमती पूजा कश्यप साहू ने बताया कि महिला समूहों को कृषि विज्ञान केंद्र, धमतरी में आगामी दिनों में मखाना के संग्रहण-पश्चात प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में उपज की उचित देखभाल, प्रसंस्करण और गुणवत्ता बनाए रखने की तकनीकों की जानकारी दी जाएगी, ताकि महिलाएं इस गतिविधि को आजीविका और उद्यमिता के रूप में आगे बढ़ा सकें।

मखाना की कटाई मुख्य रूप से तीन चरणों में की जाती है। पहली कटाई को लहसर कहा जाता है। इसमें लगभग 70 प्रतिशत मखाना निकाल लिया जाता है। इस काम के लिए श्रमिकों को सामान्यत: प्रति किलोग्राम के आधार पर मजदूरी दी जाती है। इसके बाद दूसरी और तीसरी कटाई मरकट और कर्कट कहलाती है। इन चरणों में बचे हुए लगभग 30 प्रतिशत बीज निकाले जाते हैं, जिसके लिए अधिक मेहनत और समय की जरूरत होती है। तालाब से मखाना के बीज निकालने के बाद उन्हें अच्छी तरह साफ किया जाता है। काले बीजों को धोकर लगभग 2 से 30 दिनों तक तेज धूप में सुखाया जाता है, ताकि उनकी नमी कम हो सके। इसके बाद बीजों को भट्ठी या मिट्टी की कढ़ाई में भुना जाता है। भुनाई के बाद लकड़ी की थापी से बीजों को फोड़ा जाता है। इस प्रक्रिया से बीज के अंदर का सफेद और कुरकुरा मखाना बाहर निकलता है, जिसे स्थानीय रूप से लावा कहा जाता है।

कलेक्टर श्री अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय संभावनाओं के अनुरूप कृषि की नई गतिविधियों को बढ़ावा देना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। मखाना की खेती किसानों की आय बढ़ाने के साथ महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम बन सकती है। इसके लिए, उत्पादन के साथ वैज्ञानिक तकनीक, प्रसंस्करण, गुणवत्ता और बाजार से जुड़ाव पर भी ध्यान देना जरूरी है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़े और वे आत्मनिर्भर आजीविका की दिशा में आगे बढ़ें।

मखाना उत्पादन की यह पहल धमतरी जिले में पारंपरिक कृषि गतिविधियों के साथ नए विकल्प जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उचित प्रशिक्षण, गुणवत्ता आधारित प्रसंस्करण और बाजार से बेहतर जुड़ाव मिलने पर यह पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमिता के नए अवसर पैदा करने में सहायक होगी।

सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

रायपुर, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य की भाजपा सरकार को घेरा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने एसीबी और ईओडब्ल्यू के आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि सरकार के कार्यकाल में रिश्वतखोरी बढ़ी है। उन्होंने राजस्व, स्कूल शिक्षा और पंचायत विभागों में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।

28 अक्टूबर को जारी बयान में सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरकार एक ओर सुशासन, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने दावा किया कि आम लोगों को अपने काम कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग में नामांतरण और जमीन डायवर्शन से जुड़े कामों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, स्कूल शिक्षा विभाग में तबादलों और पंचायत विभाग में विकास

कार्यों को लेकर भी उन्होंने अनियमितताओं के आरोप लगाए।

वर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं और कई जगहों पर कमीशनखोरी की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी दफ्तरों में बिना कथित सुविधा शुल्क के काम कराना मुश्किल हो गया है। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में उन्होंने अपने बयान में विभागवार विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए।

सुरेंद्र वर्मा ने एसीबी और ईओडब्ल्यू के रिकॉर्ड का उल्लेख करते हुए सरकार से भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकारी विभागों में कथित रिश्वतखोरी पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई सीमित स्तर तक रह जाती है, जबकि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं होती। कांग्रेस प्रवक्ता ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने और आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने की मांग की। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान ऑनलाइन पोर्टल और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बिचौलियों की भूमिका फिर बढ़ रही है।

वर्मा ने कहा कि राजस्व, शिक्षा और पंचायत जैसे आम जनता से सीधे जुड़े विभागों में शिकायतों का प्रभावी निराकरण जरूरी है। उन्होंने राज्य सरकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, जवाबदेही तय करने और सरकारी सेवाओं को पारदर्शी बनाने की मांग की।

नोट- कांग्रेस के बयान में लगाए गए आरोप पार्टी के दावे हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू के आंकड़ों का विस्तृत विवरण तथा राज्य सरकार का इस संबंध में पक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया है।

बिलासपुर में तालिबानी सजा, तोड़फोड़ के आरोपी को व्यापारी और गार्ड ने पीटा, पुलिस जांच में जुटी

बिलासपुर, (एजेंसी)। न्यायधानी बिलासपुर के तारबाहर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजीव प्लाजा स्थित एक प्रसिद्ध डोसा दुकान में तोड़फोड़ और चोरी की कोशिश करने के आरोपी युवक की तालिबानी अंदाज में लाठी-डंडों व लात-घूंसों से बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है।

इस पूरी घटना का एक सनसनीखेज वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक असहाय युवक को पीटते नजर आ रहे हैं और आसपास खड़े लोग मूकदर्शक बने हुए हैं। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार की बताई जा रही है। दुकान में तोड़फोड़ व चोरी का प्रयास राजीव प्लाजा स्थित डोसा दुकान में विक्की मानिकपुरी नामक युवक ने कथित तौर पर घुसकर तोड़फोड़ की और चोरी करने की कोशिश की।

दुकान में तोड़फोड़ की भनक लगते ही वहां मौजूद व्यापारी और सुरक्षा गार्डों ने विक्की मानिकपुरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद शाहन चंद्रा ने तारबाहर थाने में युवक के खिलाफ लिखित

शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की थी।

घटना के दो दिन बाद, 27 अक्टूबर को इस पूरी मारपीट का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति युवक को लाठी-डंडों, लात और घूंसों से लगातार पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य सुरक्षाकर्मी और लोग आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं।

सीएसपी गगन कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने निष्पक्ष जांच शुरू कर दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। 27 अक्टूबर को सामने आए वीडियो के आधार पर मारपीट की परिस्थितियों और उसमें शामिल व्यापारी, गार्ड तथा अन्य लोगों की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर मारपीट करने वालों पर भी वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किसना ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में अपना एक्सक्लूसिव शोरूम खोला

राज्य में यह कंपनी का 7वां एक्सक्लूसिव शोरूम है

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वैलरी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में, बनारस रोड पर अंबिका पेट्रोल पंप के पास अपने 7वें एक्सक्लूसिव शोरूम के भव्य उद्घाटन की घोषणा की। इस उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री टी. एस. सिंहदेव, पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय अग्रवाल और हरि कृष्णा ग्रुप के संस्थापक घनश्याम ढोलकिया शामिल हुए। यह किसना के रिटेल विस्तार में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हरि कृष्णा ग्रुप के संस्थापक घनश्याम ढोलकिया ने कहा कि, ₹अंबिकापुर में हमारी मौजूदगी, पूरे छत्तीसगढ़ में अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के किसना के संकल्प को और मजबूत करती है। राज्य में अपने 7वें एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, हम अपनी बेहतरीन डायमंड और गोल्ड ज्वैलरी के जरिए यहां के लोगों के त्योहारों और खास मौकों का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं। यह विस्तार हमें हमारे 'हर घर किसना' के विजन के और करीब लाता है, जिसका उद्देश्य हर भारतीय परिवार तक डायमंड ज्वैलरी पहुंचाना है। किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वैलरी के सीईओ पराग शाह ने कहा, दिवाली उपहार देने और ज्वैलरी खरीदने का एक अहम मौका है, ऐसे में हमें खुशी है कि हम अंबिकापुर के ग्राहकों के लिए किसना को लेकर आए हैं। हमारे विविध कलेक्शन और शानदार फेस्टिव ऑफर्स के जरिए, हम डायमंड और गोल्ड ज्वैलरी चुनने के अनुभव को और भी खास बनाना चाहते हैं - चाहे ग्राहक अपनी परंपराओं का जश्न मना रहे हों या जीवन की किसी नई शुरूआत का। किसना के एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट पार्टनर, राहुल गर्ग और कृष्ण अग्रवाल ने कहा, हमें अंबिकापुर में किसना को लाकर बहुत खुशी

हो रही है। हरि कृष्ण ग्रुप की विरासत और विशेषज्ञता वाले ब्रांड से जुड़ना हमारे लिए गर्व की बात है। हम अपने शोरूम में ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं, जहां उन्हें डायमंड और गोल्ड ज्वैलरी का बेहतरीन कलेक्शन मिलेगा। हमें उम्मीद है कि हमारा शोरूम लोगों के लिए त्योहारों, उपहार देने और जीवन के खास मौकों के लिए एक पसंदीदा जगह बनेगा। इस भव्य लॉन्च के अवसर पर, किसना

शानदार ऑफर लेकर आया है। इसमें डायमंड और सोने के आभूषणों की मेकिंग चार्ज (बनाने की लागत) पर 100% तक की छूट और केवल 25% डाउन पेमेंट पर 'डबल गोल्ड रेट प्रोटेक्शन' शामिल है। ग्राहक अपना पुराना सोना एक्सचेंज कर सकते हैं और डायमंड ज्वैलरी की खरीदारी पर उसकी 105% वैल्यू पा सकते हैं। इसके अलावा, किसना डायमंड ज्वैलरी (मेकिंग चार्ज सहित) पर 90% बायबैक और 95% एक्सचेंज की सुविधा दे रहा है। साथ ही, ग्राहकों को 'ग्रैंड लकी ड्रॉ' में हिस्सा लेने का मौका भी मिल रहा है, जिसमें वे कार या स्कूटर जीत सकते हैं। (नियम और शर्तें लागू)। समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए, किसना ने लॉन्च के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। इस पहल में 'स्वच्छ भारत अभियान' के समर्थन में स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान और रक्तदान शिविर भी शामिल थे। ये गतिविधियाँ सामुदायिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति किसना की प्रतिबद्धता को दशार्ती हैं।

ग्राम खोखनिया में लगातार बारिश से धान की फसल पर संकट, किसान चिंतित

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बलरामपुर। जिले के ग्राम खोखनिया में लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। 28 अक्टूबर से जारी बारिश के कारण धान की फसल को नुकसान की स्थिति बन गई है। खेतों में जलभराव से कटी और खड़ी दोनों तरह की फसल प्रभावित हो रही है।

कटाई के समय बारिश बनी आफत

इन दिनों धान की फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कई किसानों ने कटाई शुरू कर दी थी, तो कई जगह फसल खेत में ही खड़ी है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। इससे पकी फसल के गिरने, दाने में अंकुरण आने और सड़ने की आशंका बढ़ गई है। हार्वेस्टर से कटाई भी नहीं हो पा रही है।

किसान शिवनारायण जायसवाल ने जताई चिंता

ग्राम खोखनिया के किसान शिवनारायण जायसवाल ने बताया कि इस बार फसल अच्छी थी, लेकिन ऐन कटाई के वक्त बारिश ने पूरी मेहनत पर पानी फेरने जैसी स्थिति बना दी है। उन्होंने कहा कि अगर 1-2 दिन और बारिश हुई तो धान की गुणवत्ता खराब हो जाएगी और समर्थन मूल्य पर बेचने में दिक्कत आएगी। खेत में गिरे धान को निकालने में मजदूरी खर्च भी बढ़ेगा।

चक्रवात अर्नब का असर

मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात अर्नब के प्रभाव से उत्तर छत्तीसगढ़ सहित बलरामपुर जिले में बारिश की स्थिति बनी है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि जहां तक संभव हो कटी फसल को सुरक्षित स्थान पर ढक कर रखें और खेतों से पानी निकासी की व्यवस्था करें। किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और उचित मुआवजे की मांग की है।

दशमेश पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों को दी गई सुरक्षा कानूनों की जानकारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सुरक्षित बचपन जागरूकता अभियान के तहत दशमेश पब्लिक स्कूल, अंबिकापुर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देश और जिला कार्यक्रम अधिकारी जे.आर. प्रधान के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम, गुड टच-बैड टच और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी गई।

गुड टच-बैड टच की पहचान सिखाई

नालसा के सुरक्षित बचपन अभियान के उद्देश्यों पर जानकारी देते हुए बताया गया कि बच्चों को यौन शोषण और अनुचित व्यवहार से बचाना परिवार, स्कूल और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श में अंतर समझाया गया और किसी भी असहज स्थिति में बिना डर के माता-पिता, शिक्षकों या विश्वसनीय व्यक्ति को बताने के लिए प्रेरित किया गया।

पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधान बताए

विद्यार्थियों को बताया गया कि पॉक्सो कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन हमले और अश्लील उद्देश्यों से संरक्षण देता है। ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की व्यवस्था है। बच्चों को अनुचित व्यवहार पहचानने और सहायता लेने के तरीके भी बताए गए।

हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी गई। सखी वन स्टॉप सेंटर और महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से गिरवर सिंह राजपूत, कल्पना भगत, नीरज फेलिक्स कुजूर, मिशन शक्ति की जिला समन्वयक नूतन सिंह, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ नेहा सिंह राजपूत सहित प्राचार्य, शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

स्पेशल कैंपेन 6 में एसईसीएल ने लक्ष्य किया पार, स्क्रैप से 26.17 करोड़ की कमाई

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) ने केंद्र सरकार के स्पेशल कैंपेन 6 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तय लक्ष्यों को समय से पहले पार कर लिया है। स्वच्छता से लेकर स्क्रैप निपटान और रिकॉर्ड प्रबंधन तक हर मोर्चे पर कंपनी ने बढ़त हासिल की है।

226 स्थलों पर 47 लाख वर्गफुट में चला स्वच्छता अभियान

अभियान के तहत एसईसीएल ने 225 स्थलों पर सफाई का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले 226 स्थलों पर स्वच्छता गतिविधियां संचालित की गईं। 40 लाख वर्गफुट सफाई के लक्ष्य के विरुद्ध 47 लाख वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में सफाई की गई। इससे कार्यस्थल स्वच्छ और व्यवस्थित हुए हैं।

स्क्रैप निपटान से 26.17 करोड़ का राजस्व

एसईसीएल ने 3,300 मीट्रिक टन स्क्रैप निपटान के लक्ष्य के मुकाबले 4,602 मीट्रिक टन स्क्रैप का निपटान किया। इससे कंपनी को करीब 26.17 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। यह संसाधनों के बेहतर उपयोग और कार्यस्थलों के प्रभावी प्रबंधन का उदाहरण है।

फाइल प्रबंधन में रिकॉर्ड तोड़ काम

भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों के प्रबंधन में भी एसईसीएल ने लक्ष्य से कई गुना ज्यादा काम किया है।

भौतिक फाइल समीक्षाः लक्ष्य 500, समीक्षा 2,100 फाइलों की

भौतिक फाइल छंटनीः लक्ष्य 200, हटाई गईं 872 फाइलें

ई-फाइल समीक्षाः लक्ष्य 7,000, समीक्षा 14,215 ई-फाइलों की

ई-फाइल बंद करनाः लक्ष्य 3,000, निस्तारण 13,708 ई-फाइलों का

इससे प्रशासनिक कामकाज तेज हुआ है और लंबित मामलों का निपटारा हुआ है।

वेस्ट टू वेल्थ पहलः कबाड़ से बना ई वेस्ट बिन

स्पेशल कैंपेन 6 में ई-वेस्ट प्रबंधन पर विशेष जोर है। एसईसीएल मुख्यालय बिलासपुर में कर्मचारियों के पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने के लिए विशेष बिन लगाया गया है। खास बात यह है कि यह बिन भी अनुपयोगी सामग्री से बनाया गया है, जो 'वेस्ट टू वेल्थ' की अवधारणा को साकार करता है। विभिन्न क्षेत्रों में भी ई-वेस्ट संग्रहण अभियान चल रहा है। गौरतलब है कि स्पेशल कैंपेन 6 का क्रियान्वयन चरण 2 से 31 अक्टूबर तक चल रहा है।

8 निरीक्षकों समेत 73 पुलिसकर्मियों का तबादला, साइबर सेल और शिकायत शाखा में भी बदलाव

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जारी आदेश में कुल 73 अधिकारियों-कर्मचारियों की पदस्थापना बदली गई है। इसमें 8 निरीक्षक, 2 उपनिरीक्षक, 8 सहायक उपनिरीक्षक और 55 प्रधान आरक्षक, महिला आरक्षक व आरक्षक शामिल हैं। सभी को आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नई जगह तैनात किया गया है। रक्षित केंद्र में पदस्थ निरीक्षक रमेश पटेल को रामानुजनगर, सत्यनारायण देवांगन को रमकोला, मिलन सिंह को चांदनी और ढाल सिंह साहू को जयनगर थाना प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षक रंजीत प्रताप सिंह को एसपी कार्यालय में शिकायत शाखा प्रभारी, नंदकिशोर गौतम को रीडर टू एसपी, रूपेश कुंतल एक्का को साइबर सेल प्रभारी और जावेद मियांदाद को डीसीबी, डीसीआरबी और कंट्रोल रूम प्रभारी बनाया गया है। जयनगर टीआई अमित गुप्ता को बसदेई चौकी प्रभारी, रमकोला टीआई हीरालाल साहू को सूरजपुर थाना और साइबर सेल के एएसआई अरुण गुप्ता को करंजी चौकी प्रभारी बनाया गया है। 7 एएसआई की भी पदस्थापना बदली गई है। अमरेश सिंह को साइबर सेल, वरुण तिवारी को जयनगर, पास्कल लकड़ा को रामानुजनगर, बबिता यादव को विश्रामपुर, राकेश यादव को प्रतापपुर, हरिशंकर तिवारी को चंदौरा और सुनील भारती को भटगांव भेजा गया है। बड़ी संख्या में रक्षित केंद्र से थानों में भेजा गया है। रामानुजनगर, सूरजपुर, प्रतापपुर, विश्रामपुर, जयनगर, बसदेई, लटोरी, सलका-उमेश्वरपुर चौकियों में तैनाती बदली गई है। सुनील लकड़ा, हंसराम कनेडिया को रामानुजनगर, नवीन सिंह को यातायात, ममता केरकेट्टा, रोशनी सिंह को सूरजपुर थाना, अंजना एक्का को बसदेई, प्रीति भगत को प्रतापपुर भेजा गया है।

लुण्ड्रा विधायक ने 3.68 करोड़ के विकास कार्यों का किया भूमिपूजन

लमगांव में बनेगा उप स्वास्थ्य केंद्र, डडगांव-दोरना सड़क से ग्रामीणों को मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में अधोसंरचना विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर तेजी से काम हो रहा है। इसी कड़ी में सरगुजा जिले के लुण्ड्रा विकासखंड में आज दो अहम विकास कार्यों का भूमिपूजन हुआ। लुण्ड्रा विधायक प्रबोध मिंज ने ग्राम पंचायत लमगांव और डडगांव में कुल 3 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन किया। इन कार्यों के पूरा

होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य और सड़क सुविधा दोनों में बड़ी राहत मिलेगी।

लमगांव में 32 लाख से बनेगा नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र

विधायक ने लमगांव में 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का भूमिपूजन किया। केंद्र बनने से स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार, टीकाकरण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को अब छोटे इलाज के लिए लुण्ड्रा या अम्बिकापुर नहीं जाना पड़ेगा।

डडगांव से दोरना तक 3.36 करोड़ से 2 किमी सड़क

डडगांव से दोरना तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 3.36 करोड़ रुपए स्वीकृत हैं। यह सड़क डडगांव, दोरना सहित आसपास के कई गांवों को जोड़ेगी। बरसात में कीचड़ और आवागमन की दिक्कत खत्म होगी, किसानों को मंडी तक उपज ले जाने और बच्चों को स्कूल जाने में सुविधा होगी। विधायक प्रबोध मिंज ने कहा कि लुण्ड्रा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक पक्की सड़क और स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव, विधायक प्रतिनिधि जयंत मिंज, लमगांव, दोरना, डडगांव के सरपंच, जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

सरस्वती शिशु मंदिर में सुरक्षित बचपन जागरूकता कार्यक्रम, 250 विद्यार्थियों को दी बाल अधिकारों की जानकारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सरस्वती शिशु मंदिर, अंबिकापुर में ह्यसुरक्षित बचपनह्ल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी जे.आर. प्रधान के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, सुरक्षा कानूनों और हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में 250 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए।

पॉक्सो, साइबर सुरक्षा और बाल विवाह रोकथाम पर जानकारी

विधिक सेवा प्राधिकरण की नीलम बनसोडे ने बच्चों को कानूनी सहायता, नालसा की बाल हितैषी योजनाओं और हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में बताया। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सुमंती खाखा ने पॉक्सो अधिनियम, बाल विवाह रोकथाम, साइबर सुरक्षा और स्पॉन्सरशिप योजना पर जानकारी दी। उन्होंने असुरक्षित परिस्थितियों की पहचान, साइबर अपराधों से बचाव और शोषण की स्थिति में सहायता लेने के तरीके बताए। मिशन शक्ति की जिला समन्वयक नूतन सिंह ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्यों, बालिकाओं की शिक्षा और समान अवसरों पर प्रकाश डाला। नेहा सिंह ने वित्तीय साक्षरता और अनुशासन के महत्व पर चर्चा की।

हेल्पलाइन की दी जानकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि किसी भी परेशानी, हिंसा या शोषण की स्थिति में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181 और विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद ली जा सकती है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, बाल विवाह और लैंगिक भेदभाव जैसी कुरीतियों को रोकना और बालिकाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना रहा।

सम्पादकीय

सिर्फ हंगामे की बजाय ठोस प्रमाण दे विपक्ष

लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन हर विरोध को विश्वसनीय बनाने के लिए तथ्यों और प्रमाणों की कसौटी पर खरा उतरना भी जरूरी है। चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाना जितना आसान है, उतना ही महत्वपूर्ण उन सवालों के पीछे ठोस आधार प्रस्तुत करना है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष जिस तरह चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है, उसमें राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़कर प्रमाणों के साथ अपना पक्ष रखने की जरूरत है। चुनावी सुधारों को संदेह के घेरे में खड़ा करना और पूरी व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाना गंभीर विषय है। यदि कहीं अनियमितता हुई है तो उसे तथ्यों के साथ उजागर किया जाना चाहिए, लेकिन आशंकाओं को ही आरोप और आरोपों को ही सच मान लेना लोकतांत्रिक विमर्श को कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई ने विपक्ष को अपने दावों की पुष्टि करने का अवसर दिया है। अब उसे सिर्फ हंगामे या शोर से नहीं, बल्कि ठोस प्रमाणों से अपनी बात साबित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया। अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि आयोग ने एक दिन पहले ही अपना जवाब दाखिल किया है, इसलिए उसका अध्ययन करने के लिए समय चाहिए। इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, 'हमें सब पता है। हम जांच करेंगे।' इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि अदालत मामले को गंभीरता से सुन रही है। चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में एसआईआर से जुड़े फैसलों को तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिया गया बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी के हस्ताक्षर वाले हलफनामे में आयोग ने यह भी कहा कि फाइलों पर दर्ज सवाल, सुझाव या आपत्तियां अपने आप में अंतिम निर्णय के विरोध का प्रमाण नहीं हैं। आयोग के मुताबिक, एसआईआर के फॉर्म-6 में उसने कोई बदलाव नहीं किया है और नियमों के अनुसार उसमें संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। आयोग ने मतदाताओं की सुविधा और प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण भी दिए हैं। जिन मतदाताओं के नाम का पुरानी मतदाता सूची से मिलान नहीं हो पाया है, उनके जरूरी दस्तावेज बीएलओ घर जाकर जुटा सकेंगे और ऑनलाइन अपलोड करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के संबंध में आयोग ने संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने जैसी प्रक्रिया और आधार लागू होते हैं। दूसरी ओर, विपक्ष को भी यह बताना होगा कि उसकी आपत्तियां किन तथ्यों पर आधारित हैं, कहां नियमों का उल्लंघन हुआ है और किन मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं। केवल आशंका जताने या राजनीतिक आरोप लगाने से किसी दावे की पुष्टि नहीं होती। कुल मिलाकर मतदाता सूची का शुद्धिकरण लोकतंत्र की आवश्यकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का मताधिकार प्रभावित नहीं होना चाहिए। विपक्ष को समझना होगा कि केवल हंगामा करने से संदेह प्रमाण में नहीं बदलते। यदि अनियमितता हुई है तो उसके ठोस प्रमाण दें। सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए चुनावी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर अनावश्यक चोट करने से बचें।

भाजपा बनाम कांग्रेस
डॉ. घनश्याम बादल

विचारधारा, मतभेद, बदजुबानी और टकराव

लोकतंत्र में विचारों का टकराव स्वाभाविक है, लेकिन जब विचारों की जगह विद्वेष, तर्क की जगह तंज और राजनीतिक विरोध की जगह व्यक्तिगत चरित्रहनन ले ले, तब समझ लेना चाहिए कि राजनीति अपनी मर्यादा खो रही है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच वैचारिक संघर्ष पुराना है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह संघर्ष जिस तरह कटुता, अमर्यादित भाषा और संस्थाओं पर अविश्वास तक पहुंचा है, वह लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। सवाल यह नहीं कि कौन-सा दल सही है और कौन गलत; सवाल यह है कि सत्ता और विपक्ष की लड़ाई में देश की सामाजिक एकता कहीं दांव पर तो नहीं लग रही? कांग्रेस और भाजपा दो अलग राजनीतिक धाराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कांग्रेस की वैचारिक परंपरा स्वतंत्रता आंदोलन, धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद, सामाजिक न्याय और विविधता में एकता की अवधारणा से जुड़ी रही है तो भाजपा की राजनीति सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, राष्ट्रीय अस्मिता, मजबूत नेतृत्व और एकात्म मानववाद की वैचारिक धारा से प्रेरणा लेती है। इन दोनों विचारधाराओं के बीच मतभेद होना अस्वाभाविक नहीं। लोकतंत्र में यही मतभेद विकल्प पैदा करते हैं मगर समस्या तब शुरू होती है, जब कोई दल अपनी विचारधारा को ही राष्ट्रभक्ति का प्रमाणपत्र बताने लगे और विरोधी विचारधारा को देश-विरोध का पर्याय बना दे। राष्ट्र कोई एक दल, विचार या नेता नहीं है।

कांग्रेस के समर्थक भी उतने ही भारतीय हैं, जितने भाजपा के समर्थक; और किसी दल का विरोध करना अपने आप में राष्ट्र का विरोध करना नहीं है। विडंबना यह है कि दोनों दल लोकतंत्र, संविधान और देशहित की दुहाई देते हैं, लेकिन उनके नेताओं की भाषा बार-बार इन्हीं मूल्यों पर चोट करती दिखाई देती है। सत्ता से सवाल पूछना विपक्ष का धर्म है और विपक्ष की आलोचना का उत्तर देना सरकार की जिम्मेदारी। किंतु आलोचना और अपमान के बीच एक महीन रेखा है। उस रेखा को लांघते ही बहस का स्तर गिरता है और लोकतांत्रिक संवाद की जगह शत्रुता लेने लगती है। नेता भूल जाते हैं कि उनके शब्द केवल विरोधी दल तक सीमित नहीं रहते; वे समाज के व्यवहार, युवाओं की भाषा और आम नागरिकों की सोच को भी प्रभावित करते हैं। इसी कटु राजनीतिक वातावरण में एसआईआर यानी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे मुद्दे टकराव का कारण बन रहे हैं। मतदाता सूची की शुद्धता चुनावी लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। फर्जी, दोहराव वाले या अपात्र नामों को हटाना और पात्र मतदाताओं का नाम सुनिश्चित करना निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। दूसरी ओर, यदि पुनरीक्षण की प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का नाम छूटने, दस्तावेजों की कठिनाइयों या वास्तविक मतदाताओं के मताधिकार से वंचित होने की आशंका पैदा होती है, तो उस पर सवाल उठाना भी उतना ही आवश्यक है। इसलिए एसआईआर को केवल सरकार या निर्वाचन व्यवस्था के समर्थन-विरोध का प्रश्न बनाना उचित नहीं। प्रक्रिया पारदर्शी हो, पात्र मतदाताओं को पर्याप्त अवसर मिले, आपत्तियों का निष्पक्ष निस्तारण हो और गलतियों के सुधार की प्रभावी व्यवस्था हो-ये सभी पक्ष लोकतंत्र के हित में हैं। विपक्ष को बिना प्रमाण हर कार्रवाई को साजिश नहीं बताना चाहिए, तो निर्वाचन व्यवस्था को भी आलोचनाओं का उत्तर तथ्यों और पारदर्शिता से देना चाहिए। मताधिकार पर अविश्वास की स्थिति लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकती है। एसआईआर के अतिरिक्त चुनावी निष्पक्षता, संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका, आरक्षण, जातिगत गणना, धार्मिक पहचान, नागरिकता और केंद्र-राज्य संबंधों जैसे मुद्दों पर भी राजनीतिक खींचतान तीखी हुई है। अंततः, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों को याद रखना चाहिए कि विचारधाराएं लोकतंत्र को दिशा देती हैं, जबकि अहंकार और बदजुबानी उसे कमजोर करते हैं। भारत की शक्ति उसकी विविधता, सहिष्णुता और संवाद की परंपरा में है। राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को शत्रु मानने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना समय की मांग है। देश की एकता और अखंडता केवल नारों से सुरक्षित नहीं रहती; उन्हें व्यवहार, भाषा और निर्णयों में भी उतारना पड़ता है। अस्तु, लोकतंत्र में लड़ाई विचारों की होनी चाहिए, व्यक्तियों के अपमान की नहीं; नीतियों की होनी चाहिए, नागरिकों को बांटकर वोट झपटने की नहीं। सत्ता बदल सकती है, सरकारें आ-जा सकती हैं और विचारधाराओं के बीच संघर्ष चलता रह सकता है, लेकिन यदि इस संघर्ष में समाज का विश्वास, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मर्यादा टूट गई, तो जीत भले ही किसी किसी दल की नहीं हो जाए, पर, हार पूरे देश की होगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

मुद्दा
प्रो. (डॉ.) मनोज दयाल

एआई आधारित साइबर अपराध की चुनौती

> शेयर बाजार की स्क्रीन पर हरा रंग...! उम्मीद जगाता है...! पर उसी स्क्रीन के पीछे एक अदृश्य युद्ध भी चल रहा है। यह युद्ध टैंकों का नहीं। मिसाइलों का भी नहीं। यह तो एल्गोरिदम का युद्ध है। कृत्रिम मेंधा ने जहां बाजार को तेज किया है, पारदर्शिता लाया है और समावेशी बनाया है। वहीं, इसी एआई ने साइबर अपराध को एक स्वचालित, बुद्धिमान और अजेय-सा हथियार भी दे दिया है। यही कारण है कि आज एआई आधारित साइबर अपराध, बैंक खाते की चोरी से कहीं आगे निकल कर, भारत के पूंजी बाजार की स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पूंजी बाजार के लिए अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। बैंक में सेंध लगती है, तो एक ग्राहक प्रभावित होता है।

शेयर बाजार की स्क्रीन पर हरा रंग...! उम्मीद जगाता है...! पर उसी स्क्रीन के पीछे एक अदृश्य युद्ध भी चल रहा है। यह युद्ध टैंकों का नहीं। मिसाइलों का भी नहीं। यह तो एल्गोरिदम का युद्ध है। कृत्रिम मेंधा ने जहां बाजार को तेज किया है, पारदर्शिता लाया है और समावेशी बनाया है। वहीं, इसी एआई ने साइबर अपराध को एक स्वचालित, बुद्धिमान और अजेय-सा हथियार भी दे दिया है। यही कारण है कि आज एआई आधारित साइबर अपराध, बैंक खाते की चोरी से कहीं आगे निकल कर, भारत के पूंजी बाजार की स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। पूंजी बाजार के लिए अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। बैंक में सेंध लगती है, तो एक ग्राहक प्रभावित होता है।

बाजार में सेंध लगती है, तो 11 करोड़ डीमैट खाताधारकों का भरोसा डगमगा जाता है। एआई अपराध की यही मारक क्षमता इसे सबसे बड़ा खतरा बनाती है। कैसे करता है वार? पहला, डीपफेक मैनिपुलेशन। मान लीजिए किसी दिग्गज कंपनी के सीईओ का डीपफेक वीडियो बनाकर यह फैला दिया जाए कि कंपनी के नतीजे खराब हैं। वह दिवालिया होने वाली है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होते ही पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। निवेशक मिनटों में हजारों करोड़ गंवा देंगे। यह अब कल्पना नहीं...! 2024 में अमेरिकी बाजार में एक बड़ी कंपनी के साथ ऐसा प्रयास हो चुका है। दूसरा, हाइपर-पर्सनलाइज्ड फिशिंग। पहले फर्जी ईमेल की भाषा टूटी-फूटी होती थी। अब एआई आपके ट्रेडिंग व्यवहार, आपके ब्रोकर का नाम, आपके पोर्टफोलियो का विश्लेषण कर आपके ही ब्रोकर की भाषा में ईमेल बनाता है - 'आपका ट्रेडिंग अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए रोका गया है। तुरंत इस लिंक पर केवाईसी करें।' एक क्लिक और आपका पासवर्ड, ओटीपी सब हैकर के पास। तीसरा, एल्गो-स्पूफिंग। एआई बॉट्स एक सेकंड में हजारों नकली खरीद-बिक्री के ऑर्डर लगाकर किसी शेयर की कीमत को कृत्रिम रूप से ऊपर-नीचे करते हैं। आपके स्टॉप-लॉस को ट्रिगर कराते हैं। आपको बाजार से बाहर कर अपना मुनाफा कमा लेते हैं। यह माइक्रो-सेकंड का लूटतंत्र है। इसे ही इंसानी आंख पकड़ ही नहीं सकती। यही वजह है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि पूंजी बाजार अब केवल 'मार्केट रिस्क' से नहीं, 'साइबर सिस्टमिक रिस्क' से भी जूझ रहा है। एनएसई की अति सराहनीय पहल है। एएनएमआई के साथ मिलकर विशेष कार्यबल का आह्वान इस चुनौती की गंभीरता को समझते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने रक्षात्मक से आगे बढ़कर आक्रामक सुरक्षा की रणनीति अपनाई है।

एनएसई के प्रमुख ने हाल ही में एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (एएनएमआई) के सदस्यों के साथ बैठक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आह्वान किया है -'साइबर सुरक्षा पर एक विशेष संयुक्त कार्यबल का गठन।' इस कार्यबल का उद्देश्य क्या होगा? केवल दिशा-निर्देश जारी करना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ब्रोकर हाउस की साइबर सुरक्षा को मजबूत करना। एक्सचेंज अकेले सुरक्षित नहीं हो सकता, जब तक उसका हर सदस्य, हर टर्मिनल सुरक्षित न हो। एनएसई प्रमुख का स्पष्ट संदेश था - 'एक्सचेंज की सुरक्षा उतनी ही मजबूत है, जितना उसका सबसे कमजोर ब्रोकर।'

इसलिए अब एक्सचेंज और ब्रोकर एक ही टीम के रूप में इस खतरे से लड़ेंगे। यह एक स्वागतयोग्य बदलाव है।यहां नियामक केवल दंड नहीं, बल्कि साझेदारी की बात कर रहा है। एक से तीन वर्ष का रोडमैप करने की काबिलेतारीफ पहल। हर सदस्य की तकनीकी जांच और सुरक्षा कवच। इस कार्यबल का सबसे व्यावहारिक और प्रभावी पहलू इसका समयबद्ध रोडमैप है। योजना के तहत सदस्यों का चरणबद्ध मार्गदर्शन किया जाने का प्रावधान है जिसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अगले एक से तीन वर्षों में एएनएमआई के सभी सदस्यों को उचित साइबर मार्गदर्शन मिले, उनकी तकनीकी कमजोरियों की गहन जांच हो। उन्हें भविष्य के खतरों से सुरक्षित रखा जाए। यह कैसे संभव होगा? वर्ष 1 में ऑडिट और जागरूकता का उद्देश्य है। सभी सदस्यों के सिस्टम का साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, उनके कर्मचारियों के लिए डीपफेक और फिशिंग पहचान का प्रशिक्षण। छोटे शहरों के सब-ब्रोकर, जो अक्सर पुराने सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, उनकी पहचान और प्राथमिक सहायता। वर्ष 2 में अपग्रेडेशन और मानकीकरण पर बल देने की योजना है। कमजोर पाए गए सिस्टम को अनिवार्य रूप से अपग्रेड करना, सभी टर्मिनलों पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और एंड-टू-एंड एंक्रिप्शन को अनिवार्य बनाना। ड्रिल, यानी नकली एआई हमला करके यह परखना कि ब्रोकर हाउस कितनी जल्दी रिकवर होता है। यह एक से तीन साल का यह 'सुरक्षा कवच' कार्यक्रम भारतीय पूंजी बाजार को केवल प्रतिक्रिया देने वाला नहीं, बल्कि भविष्य के लिए तैयार रहने वाला बाजार बनाएगा। सबसे आश्चर्य की बात... ! अमेरिका और जापान जैसे विकसित देश भी इससे अछूते नहीं हैं। यह तो वैश्विक महामारी बन चुका है। समाचारपत्रों, पत्रिकाओं व एआई पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार अमेरिका में 2024 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट को हैक कर एआई-जनरेटेड पोस्ट से बिटकॉइन ईटीएफ की मंजूरी की झूठी खबर फैलाई गई, जिससे 5 मिनट में बिटकॉइन की कीमत 1,000 डॉलर उछल गई। एफबीआई के अनुसार, अमेरिका में वॉइस क्लोनिंग से सीईओ फ्रॉड के मामलों में पिछले साल 400% की वृद्धि हुई है। जापान में, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज ने माना है कि उसके ब्रोकर सदस्यों पर एआई-आधारित डी-डॉस हमले बढ़े हैं, जहां बॉट्स नकली ट्रैफिक से सिस्टम को जाम कर देते हैं ताकि उसी दौरान दूसरे रास्ते से सेंध लगाई जा सके। जब दुनिया के दो सबसे उन्नत तकनीक वाले बाजार भी इससे जूझ रहे हैं, तो भारत को और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह लड़ाई वैश्विक है और इसका समाधान भी वैश्विक सहयोग से ही निकलेगा। भविष्य की ढाल क्रिप्टोग्राफीक सुरक्षा हो सकती है? साथ साथ क्वांटम तैयारी भी।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 5 से 7 वर्षों में क्वांटम कंप्यूटर इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वे मौजूदा एसएसएल ताले को सेकंड में तोड़ देंगे। तब आज का एंक्रिप्टेड डेटा भी असुरक्षित हो जाएगा। अतः यह निचोड़ निकाल सकते हैं कि एआई आधारित साइबर अपराध कोई दूर की आशंका नहीं, बल्कि हमारे ट्रेडिंग टर्मिनल के दरवाजे पर खड़ा एक वास्तविक खतरा है। एनएसई द्वारा एएनएमआई के साथ विशेष कार्यबल का गठन, एक से तीन साल का व्यावहारिक रोडमैप और क्वांटम-रेडी सुरक्षा की तैयारी - ये तीनों कदम बताते हैं कि भारत का पूंजी बाजार इस खतरे को गंभीरता से ले रहा है। याद रखिए, बाजार में सबसे बड़ा मुनाफा तेज ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि सुरक्षित ट्रेडिंग से आता है। तकनीक के इस युग में निवेशक की सबसे बड़ी पूंजी उसका रिटर्न नहीं, उसकी सतर्कता है।

(लेखक कुशभाऊ ठाकरे विवि, रायपुर के कुलगुरु हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

जीवन-विकास का आधार सत्पुरुषार्थ

संकलित
दर्शन

यदि व्यक्ति समुचित दिशा में समुचित पुरुषार्थ करता रहे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित की जा सकती है। जीवन में सफल होने के लिए पुरुषार्थ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। पुरुषार्थ के अभाव में किसी भी उद्देश्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। पुरुषार्थ जीवन में हर समय अनिवार्य है। जीवन-विकास की आधारशिला पुरुषार्थ है, जो व्यक्ति अपने बुद्धि बल,

कदम-कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और अन्त में असफलता ही हाथ लगती है। इसके विपरीत जो जीवन में उल्लासपूर्वक सक्रिय रहते हैं, वे कभी भी असफल नहीं होते। सफल होने के लिए यह सुनिश्चित है कि व्यक्ति को तपना और खपना पड़ता है। पुरुषार्थ आत्म-विकास की रीढ़ है। जीवन में पुरुषार्थ की जो अनिवार्यता है, इसे एक क्षण के लिए भी नकारा नहीं जा सकता। कर्मबंधन से मुक्ति का हेतु ही पुरुषार्थ है। जड़ता एवं निष्क्रियता के धरातल से ऊपर उठकर जब व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो वह व्यावहारिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों से समृद्ध बनने लगता है। कोई कुछ भी करे ही नहीं एवं मन में बड़ी-बड़ी कल्पनाएं करता रहे तो केवल कल्पनाओं से कुछ भी नहीं होता। मंजिल पर पथिक तभी तो पहुँच पाएगा, जब वह लक्ष्य की ओर गतिशील होगा। पथिक अपने घर-आँगन में बैठा हुआ नक्शा देखता रहे कि अमुक गाँव इतनी दूर है, अमुक रास्ते से होकर मुझे जाना पड़ेगा। केवल इस तरह का गणित करता रहे और मंजिल की ओर एक कदम भी न बढ़ाए तो घर-आँगन में बैठे रहने से तो मंजिल मिलने से रही। मंजिल को पाने के लिए कदमों को बढ़ाना पड़ता है। यह सत्य है कि चलने वालों ने ही मंजिल से मुलाकात की है। *-कांतिलाल मांडोत*

हनुमान जी से सीखें सफल होने के मंत्र

संकलित
प्रेरणा

हिंदू धर्म में हनुमान जी को शक्ति, भक्ति, साहस और सेवा का प्रतीक माना जाता है। उनका जीवन केवल प्रभु श्रीराम के प्रति अटूट भक्ति की सीख नहीं देता, बल्कि मुश्किल समय में सही फैसला लेने, जिम्मेदारी निभाने और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा भी देता है। रामायण में हनुमान जी से

दिखाती हैं। उनके व्यक्तित्व के 8 गुण ऐसे हैं, जिन्हें अपनाकर इंसान अपने काम और रिश्तों में बेहतर बदलाव ला सकता है। हनुमान जी का संवाद कौशल उनके व्यक्तित्व की बड़ी विशेषता था। अशोक वाटिका में माता सीता से मिलते समय उन्होंने अपनी वाणी और व्यवहार से उनका विश्वास जीता। इससे सीख मिलती है कि बात केवल अपनी बात रखने की नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को समझने की भी है। सही शब्दों और विनम्र व्यवहार से कठिन बातचीत को भी आसान बनाया जा सकता है। समुद्र पार करते समय सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोक लिया था। इस बाधा को उन्होंने केवल बल से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और सूझबूझ से पार किया। उनका यह प्रसंग बताता है कि हर परेशानी का हल ताकत दिखाने में नहीं होता है। कई बार शांत रहकर परिस्थिति को समझना और समय के अनुसार फैसला लेना ही सबसे बेहतर रास्ता होता है।

अंतर्मन

आज की पाती

अनूठा लोक पर्व है छठ पूजा

भारत की सांस्कृतिक चेतना में कुछ पर्व ऐसे हैं, जिनमें लोक, धर्म, प्रकृति और तपस्या का अद्भुत संगम दिखाई देता है। छठ महापर्व उन्हीं में से एक है। यह एक ऐसा पर्व है जो अब किसी एक क्षेत्र की सीमाओं में नहीं बंधा बल्कि भारतीय आस्था के विशाल सागर में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका है। वास्तव में यह आत्मशुद्धि, संयम और कृतज्ञता की वह साधना है, जिसमें मनुष्य सूर्य और प्रकृति के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करता है। बिहार, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों से शुरू होकर अब यह पर्व देश और विदेश के असंख्य भारतीयों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। चार दिनों तक चलने वाला यह महापर्व कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से आरंभ होकर षष्ठी और सप्तमी को चरम पर पहुंचता है। *- पूनम सचदेवा, पानीपत*

करंट अफेयर

डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन कर सकते हैं ट्रंप समर्थक

अमेरिका में 2024 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने वाले कम से कम 25 प्रतिशत दक्षिण एशियाई अमेरिकी मतदाता तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों का समर्थन करने की योजना बना रहे हैं। एक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई। लोगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन 'इंडियन अमेरिकन इम्पैक्ट' द्वारा कराए गए इस सर्वेक्षण में जीवनयापन की लागत (65 प्रतिशत), स्वास्थ्य सेवा (53 प्रतिशत), रोजगार और वेतन (33 प्रतिशत) तथा शिक्षा (28 प्रतिशत) को मध्यावधि चुनावों के प्रमुख मुद्दों के रूप में पहचाना गया है। सर्वेक्षण में शामिल 800 पंजीकृत दक्षिण एशियाई मतदाताओं में से 87 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकी हैं जबकि शेष 13 प्रतिशत पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान और म्यांमा के अलावा कंबोडिया के खमेर समुदाय से संबंधित हैं। वर्ष 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को वोट देने वालों में से 96 प्रतिशत आगामी चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के पक्ष में अपना वोट डालने की योजना बना रहे हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि ट्रंप को वोट देने वाले 67 प्रतिशत दक्षिण एशियाई अमेरिकी अब भी रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं, लेकिन 25 प्रतिशत ने कहा कि वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे।

ऑफ बीट

संभवत: यूरोप में हुई थी चमगादड़ों की उत्पत्ति

दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल पर बहस करते रहे हैं कि चमगादड़ों की उत्पत्ति कहां हुई थी। 'नेचर' पत्रिका में हाल में प्रकाशित एक अध्ययन इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए नए साक्ष्य प्रस्तुत करता है। 'डीएनए' और जीवाश्मों के साथ किए गए अंतरराष्ट्रीय अध्ययन इस बात का समर्थन करते हैं कि चमगादड़ों की जन्मस्थली संभवतः यूरोप है। अब तक इस सवाल का जवाब तलाशने में एक बड़ी मुश्किल यह रही है कि पक्षियों के विपरीत, चमगादड़ों के जीवाश्मों में उनके विकास की शुरुआती अवस्थाओं के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। पक्षियों के जीवाश्मों का रिकॉर्ड इतना समृद्ध है कि उससे डायनासोर से मुर्गी तक जैसे पक्षियों एवं जानवरों के विकास की कड़ी को समझा जा सकता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों को चमगादड़ों के जीवाश्म मिलते हैं, तो वे लगभग पूरी तरह विकसित चमगादड़ों के ही होते हैं। चमगादड़ उड़ान भरने और हवा में बने रहने के लिए सक्रिय रूप से अपने पंखों का इस्तेमाल करने वाले इकलौते स्तनधारी हैं। पहले किए गए अध्ययनों में अमेरिका, अफ्रीका या एशिया को उनकी संभावित जन्मस्थली बताया गया था। अलग-अलग आंकड़ों और गणना के तरीकों से अलग-अलग नतीजे सामने आए।

ट्रेंड

प्रकाश पर्व पर बधाई

सिख धर्म के चौथे गुरु श्री रामदास के प्रकाश पर्व पर बधाई। उन्होंने अमृतसर शहर की नींव रखी और दुनिया को आस्था का एक ऐसा केंद्र दिया, जो आज भी पूरी दुनिया को सेवा और सद्भाव का संदेश दे रहा है। -अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

वोट चोरी

दिल्ली के हर व्यापारी से: हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। मेट्रो सरकार ने बंद की, सड़कें सरकार ने सील की, राजधानी पर ताला सरकार ने लगाया। जब वोट ही चोरी हो जाए, तो कुछ भी सुरक्षित नहीं - न आपकी दुकान, न आपकी बचत, न आपके बच्चों का भविष्य। - राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

युवाओं के सपने

जिन युवाओं ने कभी देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया था, वे आज बेरोजगारी के कारण अपना खून बहाने को मजबूर हैं। बीजेपी ने युवाओं के सपनों को कुचल दिया है। यूपी इस समय बेरोजगारी और काम न मिलने के संकट से गुजर रहा है। - अखिलेश यादव, सांसद, सपा

ज़िंदगी की सच्चाई

जिंदगी की सच्चाई यह है कि जिन लोगों की आप परवाह करते हैं, वे कभी न कभी आपको दुख जरूर पहुंचाएंगे। आपकी समझदारी इसी में है कि आप सोच-समझकर चुनें कि आप किसे खुद को दुख पहुंचाने की इजाजत देते हैं! - रामगोपाल वर्मा, फिल्मकार

खबर संक्षेप

आजम की 426 करोड़ की संपत्ति अटैच

प्रयागराज। प्रवर्तन निदेशालय के लखनऊ जोनल ऑफिस ने सपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के

पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों को अटैच करने की कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अटैच की गई संपत्ति की कीमत 426.46 करोड़ रुपए आंकी गई है।

फिल्म महोत्सव की अंतिम तिथि बढ़ी

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 57वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के लिए

मीडिया प्रत्यायन हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 4 नवंबर कर दी है। सिनेमा की इस नई दुनिया का अनुभव करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं।प्रत्यायन पोर्टल से फार्म जमा कर सकते हैं।

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम आमादरहा, तहसील दरिमा, जिला सरगुजा छ०ग०, प.ह.नं. 7, रा.निम. - सोहगा को सूचित किया जाता है कि विक्रेता सुशीला अग्रवाल पति धनश्याम दास अग्रवाल के द्वारा श्री विष्णु प्रसाद गोयल आ० स्व० श्री रामनिवास गोयल को 22 मार्च 2023 को बिक्रय किया गया था को कार्यालय में पुस्तक क्रमांक आई.डी. 11294Ka-01 पेज नम्बर 334 359, S.No. 6359 में अंकित है। उक्त रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र की मूल प्रति जो सुशीला अग्रवाल ने बसंती पति विजयलाल अरजुन परमान से खरीदी थी जो 22 मार्च 2022 को बिक्रय हुई थी की ऑरिजीनल कांपी कही गुम हो गई है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27.10.2026 को मणीपुर थाना अम्बिकापुर में आवेदक ने दर्ज करायी है एवं इस संबंध शपथ पत्र भी दिनांक 27.10.2026 को निष्पादित कराया गया है। यदि किसी जनसाधारण को उक्त रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र मिलते है तो जल्द से जल्द आवेदक श्री विष्णु प्रसाद गोयल को लौटा देवें। आवेदक उक्त भूमि को बंधक रखकर बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहता है। अतः उक्त रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र की वैधानिकता एवं गुम होने के सबंध में किसी भी जनसाधारण को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से 7 दिवस के भीतर बैंक में या आवेदक के समक्ष दावा आपत्ति पेश कर सकते है इसके पश्चात की गयी दावा आपत्ति मान्य नही होगी।

आवेदक
विष्णु प्रसाद गोयल
पता बिलासपुर चौक, कान्हा टायर्स आर.के. पेट्रोल पम्प के सामने अम्बिकापुर
जिला सरगुजा छ०ग०
मो.नं. 9406132991

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' ने आंध्र प्रदेश और यानम में मचाई तबाही

आंध्र प्रदेश में 5 की मौत, 50 से ज्यादा ट्रेनें और उड़ानें रद्द, कई जगह पेड़ गिरे

ओडिशा में सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया

तेज हवाओं और संभावित बाढ़ से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम

एजेंसी ▶▶ भुवनेश्वर

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' ने बुधवार सुबह आंध्र प्रदेश और यानम के तटीय इलाकों में टकराना शुरू कर दिया है, जिससे वहां भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश, तेज हवाओं और संभावित बाढ़ से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में प्रशासन ने एहतियाती कदम तेज कर दिए हैं।मौसम विभाग ने कहा कि तूफान के केंद्र में हवा की रफ्तार 125 से 135 किमी प्रति घंटा है, जो झोंकों के साथ 150 किमी प्रति घंटा तक पहुंच रही है।

पिछले तीन घंटों में तूफान 3 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है। अनुमान है कि शुरुआत में धीमी गति से उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ेगा और फिर उत्तर-उत्तर-पश्चिम की ओर रुख करेगा। बुधवार तड़के अर्णब आंध्र प्रदेश के तट के पास टकराया। इस पूरी प्रक्रिया में 6 घंटे से अधिक का समय लगा। चक्रवात से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई।

यहां भारी बारिश से बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा

मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी

भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि तूफान के जमीन की ओर बढ़ने के दौरान हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। हवा के झोंकों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है। मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगड़ा, गजपति और कालाहांडी में बेहद भारी बारिश और रेड अलर्ट जारी किया है।

रेल मंत्री रख रहे करीबी नजर

रेल पटरियों पर 10 जगह गिरे पेड़, तेजी से हटाया गया

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि'अर्नब' के टकराने के बाद रेलवे नेटवर्क पर 10 जगहों पर पेड़ गिर गए थे। राहत टीमों ने तत्परता दिखाते हुए सभी स्थानों से पेड़ों को तुरंत हटाकर ट्रैक साफ कर दिया।

नायडू ने शाह से की बात

आंध्र प्रदेश के सीएमएन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर

'अर्नब' से प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की टीमों की मदद बढ़ाने का अनुरोध किया है। केंद्र से अपील की है कि चक्रवाती तूफान से हुए जान-माल और फसलों के नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीमों को जल्द से जल्द आंध्र प्रदेश भेजने को कहा है।

आंधी से उखड़े सैकड़ों पेड़-खंभे समुद्र में फंसा सल्फर से लदा मालवाहक जहाज

आंध्र प्रदेश के अंतर्वेदी के पास समुद्र में सल्फर ले जा रहा एक मालवाहक जहाज रास्ते से भटकने के बाद उथले पानी में फंस गया। यह घटना चक्रवात अर्नब के बीच सामने आई है। जहाज विशाखापत्तनम से रवाना हुआ था। बताया जा रहा है कि इंजन में खराबी आने के बाद जहाज अपना रास्ता भटक गया और अंततः अंतर्वेदी के पास समुद्र में फंस गया। संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण के बाद जहाज की स्थिति का आकलन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

झारखंड के कई जिलों में 29 अक्टूबर तक स्कूल बंद

'अर्नब'सेभारी बारिश को देखते हुए झारखंड सरकार ने कई जिलों में 29 अक्टूबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में बुधवार और गुरुवार को स्कूल बंद रहेंगे।

कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी में उठे 'अर्नब' के प्रभाव से झारखंड में मौसम बदला है। रांची समेत कई जिलों में बुधवार सुबह से बारिश हो रही है। आईएमडी ने रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, बोकारो, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

संविधान देता है गारंटी: वैष्णव

डीपीडीपी प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता

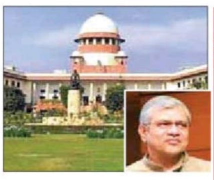

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम का कोई भी प्रावधान प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। इस कानून को लेकर मीडिया जगत में जताई जा रही व्यापक चिंताओं के बीच वैष्णव ने कहा कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। उन्होंने संपादकों और मीडिया पेशेवरों को इस अधिनियम के प्रावधानों पर सरकार के साथ खुली चर्चा के लिए आमंत्रित भी किया। वैष्णव का यह बयान डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) द्वारा एक दिन पहले डीपीडीपी अधिनियम और इसके नियमों के कुछ प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के बाद आया है।

सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई

डीएनपीए 21 समाचार प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करता है। समाचार प्रकाशकों ने दलील दी है कि इस अधिनियम में पत्रकारिता संबंधी गतिविधियों के लिए विशेष छूट नहीं दिए जाने से खोजी पत्रकारिता प्रभावित हो सकती है और प्रेस की स्वतंत्रता के समक्ष खतरा पैदा हो सकता है। उच्चतम न्यायालय नेकेंद्र से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है। समाचार संस्थानों की दलील है कि व्यक्तिगत डेटा से जुड़े नोटिस, सहमति और डेटा मिटाने संबंधी प्रावधानों के कारण पत्रकारों के लिए जनहित के मुद्दों पर रिपोर्टिंग मुश्किल हो सकता है। कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान ऐसी बाधाएं आ सकती हैं।

पत्रकारिता की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी

वैष्णव ने इन आशंकाओं पर कहा कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता की गारंटी भारत का संविधान देता है। यह स्वतंत्रता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रभावित करने की कोई मंशा भी नहीं है। इस तरह, निजता कानून पत्रकारिता की स्वतंत्रता को पूरी तरह बनाए रखता है, इसकी गारंटी संविधान देता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल निजता का अधिकार सुनिश्चित करने वाला यह कानून उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही बनाया गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा

'ब्रिंग बैक बैलेट' इंस्टा ब्लॉक केंद्र और मेटा से जवाब मांगा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'ब्रिंग बैक बैलेट' नाम के इंस्टाग्राम खाते को ब्लॉक करने के खिलाफ दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार और मेटा प्लेटफॉर्म्स से उनका पक्ष बताने को कहा है। इंस्टाग्राम हैंडल पर चुनावों में मत पत्र के इस्तेमाल का समर्थन करने वाली सामग्री प्रकाशित की जाती थी। न्यायमूर्ति अमित महाजन ने 27 अक्टूबर को अकाउंट संचालक, संगठन 'मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन' और इसके संस्थापक वकील महमूद प्राचा की याचिका पर नोटिस जारी किया और 6 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। जिस दिन संगठन ने जंतर-मंतर पर 'ब्रिंग बैक बैलेट- ईवीएम हटाओ, देश बचाओ' नाम से एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का प्रस्ताव रखा, उसी दिन उसे पता चला कि भारत में उसका 'ब्रिंग बैक बैलेट' हैंडल उपलब्ध नहीं है।

मद्रास हाईकोर्ट ने साफ की स्थिति

गैरहिंदुओं को नहीं मिलेगा मंदिर में प्रवेश, परंपरा से समझौता नहीं

एजेंसी ▶▶ चेन्नई

मद्रास हाई कोर्ट ने आगम मंदिरों में प्रवेश को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि जो गैर-हिंदू श्रद्धा व्यक्त करने का संकल्प लेने या पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करने से इनकार करते हैं, उन्हें आगम मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसा करने से मंदिरों की धार्मिक पवित्रता प्रभावित होगी। यह फैसला के थंगम वेंकटेश की जनहित याचिका के बाद आया है, जिसमें 'तमिलनाडु मंदिर प्रवेश प्राधिकरण अधिनियम' को सख्ती से लागू करने और नियमों के उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति पी मुरुगन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल आगम मंदिरों पर लागू होता है। आगम मंदिर प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बनाया जाता है, प्रतिष्ठित किया जाता है।

मंत्रिमंडल ने कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी

कंटेनर के आयात पर निर्भरता घटेगी व आपूर्ति मजबूत होगी

10,000 करोड़ रुपए के आवंटन वाली योजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी

वैष्णव ने कहा-केंद्रीय बजट में की गई थी घोषणा

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन वाली 'कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना' को मंजूरी दी। यह योजना वित्त वर्ष 2039-40 तक लागू रहेगी। योजना का उद्देश्य कंटेनर के आयात पर निर्भरता कम करना और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना है। इसके तहत नई

विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों की क्षमता बढ़ाने में सहायता दी जाएगी। देश में कंटेनर के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2026-27 में की गई थी।

योजना वित्त वर्ष 2039-40 तक लागू रहेगी

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा मंत्रिमंडल की बैठक में कंटेनर विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। यह योजना 2039-40 तक लागू रहेगी। योजना के तहत पात्र विनिर्माताओं को ब्याज सब्सिडी, परिचालन व्यय सहायता, परीक्षण प्रमाणन सहायता तथा भूमि पट्टे पर लेने के लिए सहायता दी जाएगी।

बुंदेलखंड प्रयागराज के लोकप्रिय बाहुबली भाजपा नेता नहीं रोक सके मानसिंह यादव का रथ: सिद्धार्थ पांडे

संवाददाता

चित्रकूट। जनपद के समाजवादी पार्टी के युवा नेता जिला पंचायत सदस्य सिद्धार्थ पांडे ने बताया की मोदी योगी के लोकप्रियता प्रजातंत्र में घट रही है। एम एल सी चुनाव में समाजवादी पार्टी के मानसिंह यादव ने बुंदेलखंड प्रयागराज स्नातक क्षेत्र से विजय हासिल कर लिया। बुंदेलखंड प्रयागराज में समाजवादी पार्टी का जीत का रथ नहीं रोक पाए भाजपा के लोकप्रिय बाहुबली पदाधिकारी। कहा जाता है कि मऊ मानिकपुर के वर्तमान विधायक प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट में बांदा में अपना दम दिखाने में विधायक हैं जो अरबपति हैं। पांडे ने बताया कि 2027 में समाजवादी पार्टी पूरे बुंदेलखंड, प्रयागराज, कौशांबी क्षेत्र में अपना दबदबा बनाएगी।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०-/अ-6/2026-27
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सत्येन्द्र सिन्हा आ.स्व. सिद्धेश्वर प्रसाद सिन्हा निवासी फुन्दुरडिहारी तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा ग्राम फुन्दुरडिहारी स्थित भूमि खसरा नंबर 130/37 रकबा 0.214 हे0 भूमि राजस्व अभिलेखो से मृत खातेदार पार्वती देवी पति सिद्धेश्वर, अनुराधा पिता सिद्धेश्वर, सरिता पिता सिद्धेश्वर, संगीता पिता सिद्धेश्वर एवं रोशनी सिन्हा पिता सिद्धेश्वर द्वारा अपने अपने हिस्से की भूमि को बिक्री पूर्व किये जाने का का नाम विलोपित करते हुये फौती नामांतरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 18.11.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।आज दिनांकः- 28/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०-/अ-6/2026-27
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक केशरी नन्दन सिंह पिता रामवृक्ष जाति क्षत्रीय निवासी डी 401 रॉयल राहेजा रेसीडेन्सी अपोजिट सेन्ट जेवीयर स्कूल अवन्ती विहार रायपुर जिला रायपुर छ०ग० के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 167/9, 167/7, 179/60 रकबा 0.405, 0.101, 0.310 हे0 मेसे रकबा 0.006, 0.002, 0. 002 हे0 कुल रकबा 0.010 हे. भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 22.07. 2024 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है।उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 04.11.2026 के पूर्व स्वयं अचवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः 16/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर, सरगुजा

न्यायालय नायब तहसीलदार लुण्ड्रा, जिला सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०/अ-21/2026-27
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण ग्राम लुण्ड्रा को सुचित किया जाता है कि आवेदक कलाम अंसारी आ० इशहाक, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम चिरंगा, तहसील लुण्ड्रा (धौरपुर), जिला सरगुजा (छ०ग०) द्वारा अपने स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ग्राम लुण्ड्रा में ख०नं० 182/15 रकबा 0.028 हे0 स्थित है।उक्त वादभूमि को अनावेदक सोनिया पति सुनील, निवासी ग्राम लुण्ड्रा के पास बिक्री करने की अनुमति हेतु श्रीमान कलेक्टर सरगुजा के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो जांच हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति पेश करना हो तो वह दिनांक 10/11/2026 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकता है। नियत दिनांक पश्चात प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 27/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी ।

नायब तहसीलदार
लुण्ड्रा, जिला सरगुजा (छ०ग०)

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०-/अ-6/2026-27
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ० सरिता सिंह पत्नी स्व० वेदराम सिंह जाति कंवर निवासी मकान नंबर 76, रॉयल पार्क कॉलोनी मोहल्ला पटपरिया अम्बिकापुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०म० के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 167/9 रकबा 0.405 हे0 मेसे रकबा 0.014 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2024 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 04.11.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः 16/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर, सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०-/अ-6/2026-27
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रज्ञा पटेल पत्नी धीरज कुमार जाति कुर्मी निवासी मकान नंबर 18, साई रेसीडेन्सी केन्द्रीय विद्यालय के पास भगवानपुरखुर्द अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम नमनाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 179/59 रकबा 0.295 हे0 मेसे रकबा 0.016 हे0 भूमि के राजस्व अभिलेखो में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 18.07.2024 के माध्यम से नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 04.11.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति

पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 16/10/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर, सरगुजा

चित्रकूट पुलिस ने गैंगरेप की घटना में शामिल 50 हजार रुपए के इनामिया अभियुक्त को असलहा सहित किया गिरफ़्तार

संवाददाता

चित्रकूट पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी मऊ फहद अली के कुशल पर्यवेक्षण में एसओजी एवं थाना मानिकपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने जड़ेरा जंगल झरी फाटक के पास गैंगरेप की घटना में शामिल 50 हजार रुपए के इनामिया अभियुक्त को 01 देशी राइफल 315 बोर, 06 अदद खोखा व 01 जिन्दा कारतूस, 01 चिड़िया मारने वाली बंदूक व चोरी की 02 मोटरसाइकिल व चोरी का 01 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14.07.2026 को नाबालिग पीड़िता ने थाना मानिकपुर में सूचना दी कि दिनांक 13.07.2026 को समय करीब 12.00 बजे दिन वह अपने साथी के साथ झरी फाटक से आगे करीब 1 किमी जाकर कच्चे रास्ते से जंगल की ओर चेकडैम के पास गई थी, जहाँ 03 लड़के चैकडेम नहा रहे थे उन तीनों ने पीड़िता व उसके साथी को असलहा दिखाकर डरा-धमकाकर जंगल के अंदर ले गए, साथी के दोनों हाथ पीड़िता के दुपट्टे से पीछे बांध दिए और पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में दो अभियुक्त साथी की मोटरसाइकिल की चाबी लेकर खाने-पीने का सामान लेने मानिकपुर चले गए। इसी दौरान साथी मौके से भागने में सफल रहा। वापस आने पर अभियुक्तगण पीड़िता को करीब 3-4 घंटे जंगल में रोकने के बाद उसके साथी की मोटरसाइकिल पर बैठाकर मारकुंडी, हनुमानधारा होते हुए कर्वी पेट्रोल पंप के पास छोड़ दिया और जान से मारने की धमकी देकर किसी को न बताने को कहा था। इस सूचना के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 101/2026 धारा 70(2),127(2),351(3),304(2),131 बीएनएस व 5ऋ/6 पॉक्सो एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में घटना में शामिल अभियुक्त कोतवाली देहात जनपद बांदा(25 हजार का इनामिया) को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। घटना में शामिल फरार अभियुक्त सुभाष उर्फ लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करवई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र,बांदा द्वारा 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। इसी क्रम में दिनाँक 27.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर व रडऋ की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल फरार इनामिया अभियुक्त सुभाष उर्फ लल्लू उर्फ लाला की तलाश में रवाना होकर झरी फाटक पर मौजूद थे कि मुखबिर ने आकर बताया कि वही इनामिया अभियुक्त चोरी की मोटरसाइकिल के साथ चूल्ही जाने वाले मोड़ के आस पास कोई घटना करने के फिराक में जंगल क्षेत्र में घूम रहा है जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को आवश्यक बल प्रयोग कर उसे पकड़ा गया। जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम सुभाष उर्फ लल्लू उर्फ लाला पुत्र जगजीत वर्मा निवासी करवई थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा बताया जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद एंड्रॉयड फोन वीवो ,01 आधार कार्ड व 140 रुपये बरामद हुए तथा उसके पास मिली बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल जिसको ई-चालान से चेक करने पर उसका असली नंबर वढ96व1482 होना पाया गया जो थाना मानिकपुर के मु0अ0सं0 177/26 धारा 303(2) बीएनएस की चोरी की है

बस्तर संभाग के 116 नेताओं की वीआईपी सुरक्षा में कटौती, केदार कश्यप-दीपक बैज शामिल: डिप्टी सीएम शर्मा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सल हालात में सुधार के बीच सरकार ने वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा करते हुए बड़ा फैसला लिया है। बस्तर संभाग के भाजपा-कांग्रेस के 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी कम करने की तैयारी है। इनमें कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और कवासी लखमा शामिल हैं।9 नेताओं की सुरक्षा जेड+ से घटाकर जेड की जाएगी। गृह विभाग जल्द औपचारिक आदेश जारी करेगा।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान

उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि परिस्थितियां सामान्य होने पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। नेताओं को लोकसेवक बताते हुए विशेष सुरक्षा का नए सिरे से आकलन जरूरी है। इसे पुलिस बल और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में बदलाव माना जा रहा है।

किनकी सुरक्षा घटेगी

जानकारी के अनुसार केदार कश्यप, महेश गागड़ा, दीपक बैज, कवासी लखमा और कर्मा परिवार की जेड+ सुरक्षा घटाकर जेड की जाएगी। बाकी विधायकों, सांसदों और पूर्व मंत्रियों में कुछ की सुरक्षा जेड से वाई की जाएगी। अंतिम सूची गृह विभाग के आदेश से स्पष्ट होगी।

सुरक्षा पर 150 करोड़ खर्च का दावा

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रदेश में करीब 400 नेताओं की सुरक्षा में 1550 से अधिक जवान और 500 से ज्यादा वाहन लगे हैं, जिन पर सालाना करीब 150 करोड़ रुपए खर्च होने का दावा है। जम्मू-कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ इस मामले में प्रमुख राज्यों में है। बस्तर में ही करीब 250 स्थानीय नेताओं को सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें 1000 से अधिक जवान तैनात होने का दावा है।

जीपीएम में सड़क पर दिखा दुर्लभ सफेद भालू, राहगीर थमे वीडियो वायरल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। पेंड्रा-बिलासपुर मुख्य मार्ग पर पटियाला हाउस के पास उस समय हड़कंप मच गया, जब एक दुर्लभ सफेद भालू जंगल से भटककर मुख्य सड़क और रिहायशी इलाके में आ पहुंचा। सड़क पर अचानक भालू को घूमते देख आवागमन थम गया। राहगीरों ने गाड़ियां रोक दीं और मोबाइल से वीडियो बना लिया। वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

एल्बिनिज्म के कारण सफेद है रंग

वन विशेषज्ञों के मुताबिक यह कोई नई प्रजाति नहीं है। यह भारतीय काले भालू (स्लॉथ बियर) ही है, लेकिन आनुवंशिक विकार एल्बिनिज्म (रंग वर्ण दोष) के कारण इसका रंग काला न होकर पूरी तरह सफेद हो गया है। वन विभाग के अनुसार इससे पहले भी मरवाही वनमंडल के जंगलों में इस सफेद भालू की मौजूदगी देखी जा चुकी है।

वन विभाग ने की अपील

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई और मौके पर पहुंचकर निगरानी शुरू कर दी। किसी भी मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए भालू को सुरक्षित घने जंगल की ओर मोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग ने स्थानीय लोगों और राहगीरों से अपील की है कि भालू के पास न जाएं, उसे घेरने, छेड़ने या उकसाने की कोशिश न करें।

पर्यावरण संरक्षण में स्काउट्स-गाइड्स निभाएं भूमिका: राज्यपाल

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

लोकभवन में 1122 को दिया राज्य पुरस्कार

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जल और जंगल बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं। स्काउट्स-गाइड्स जल संचयन और वनों की रक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की सराहना भी की। राज्यपाल लोकभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स द्वारा आयोजित राज्य पुरस्कार अलंकरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेशभर के 1122 स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को राज्य पुरस्कार प्रदान किए। अध्यक्षता शिक्षा मंत्री और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र यादव ने की।

बस्तर में शांति के बाद विकास तेज - राज्यपाल

राज्यपाल ने कहा कि स्काउट्स का आदर्श वाक्य 'तैयार रहो' जिम्मेदारियों के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। पुरस्कार के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बस्तर से आए स्काउट्स-गाइड्स की मौजूदगी पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद बस्तर में शांति स्थापित हुई है और क्षेत्र तेजी से विकास कर रहा है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि स्काउटिंग की वर्दी अनुशासन, सेवा और समर्पण का प्रतीक है और स्काउटिंग से जुड़ा व्यक्ति जीवनभर सेवा भाव से काम करता है।

इन 1122 को मिला सम्मान

समारोह में 405 स्काउट्स, 528 गाइड्स, 64 रोवर्स और 125 रेंजर्स को पुरस्कृत किया गया। सर्वश्रेष्ठ स्काउटर योगेश्वर प्रसाद गांगुली (बालोद), सर्वश्रेष्ठ गाइडर तनुजा बंजारे और लता वैष्णव (महासमुंद), सर्वश्रेष्ठ रोवर राजमणि बंजारे व चंद्रशेखर पंकज, सर्वश्रेष्ठ रेंजर विभूति वर्मा और कृति बिजौर, सर्वश्रेष्ठ स्काउट ईश साहू, हरीश खोटे, राजवीर भट्ट और सर्वश्रेष्ठ गाइड दिव्या पटेल व दीप्ति पटेल को सम्मानित किया गया। दीर्घकालीन सेवा के लिए शैलेंद्र मिश्रा, आनंद राम बघेल, पवन नायक, विनोद हथेल, शशि बंछोर और रजनी रेड्डी को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान लोकभवन में पदस्थ एडीसी उदित पुष्कर को रैंक बैज लगाकर सम्मानित किया गया।

मंत्री राजवाड़े के निर्देश पर 12 पर्यवेक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त

महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी किया आदेश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर विभागीय प्रक्रिया पूरी करते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ 12 पर्यवेक्षकों की विभागीय परिवीक्षा अवधि समाप्त करने का आदेश जारी किया गया है। विभागीय समिति की 12 अक्टूबर को हुई बैठक में की गई अनुशंसा के आधार पर 22 अक्टूबर को यह आदेश जारी हुआ। परिवीक्षा अवधि पूरी करने वाले पर्यवेक्षक बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद, दुर्ग और रायपुर जिले में पदस्थ हैं। इनमें श्रीमती माया यादव, सुश्री अनुका चन्द्रवंशी, सुश्री धनेश्वरी नाग, श्रीमती रितु देवांगन, सुश्री रजनी भौमना, श्रीमती संध्या साहू, श्रीमती डिम्पल साहू, श्रीमती तृप्ति शर्मा, श्रीमती अंजू सिंह, सुश्री अम्बा पटेल, सुश्री गुंजा ध्रुव और श्रीमती कंचन माहेश्वरी शामिल हैं। श्रीमती तृप्ति शर्मा के मामले में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि के आधार पर परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की कार्यवाही की गई है। यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) के तहत जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल स्थायीकरण का आदेश जारी नहीं किया गया है। पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार उन्हें स्थायी किया जाएगा।

25 हजार की रिश्वत के आरोप में पटवारी निलंबित, 7 दिन में आरोप पत्र के निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

बिलासपुर। राजस्व कार्य के लिए 25 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। पटवारी पहले हल्का नंबर 14 में पदस्थ था, वर्तमान में पचपेड़ी तहसील के हल्का नंबर 05 में कार्यरत था। तहसीलदार पचपेड़ी ने 28 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट सौंपी थी। आदेश में इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध गंभीर कदाचरण और शासन की छवि धूमिल करने वाला कृत्य बताया गया है।

जमीन बंटवारे के लिए 50 हजार में सौदे का दावा

मामला जमीन बंटवारे से जुड़ा है। वायरल वीडियो करीब 4 महीने पुराना बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मस्तूरी एसडीएम बजरंग वर्मा ने तहसीलदार प्रकाश साहू को जांच सौंपी थी। पटवारी को बयान के लिए मस्तूरी बुलाया गया, लेकिन वह नहीं आया। वीडियो में पटवारी जमीन मालिकों से पैसों के लेनदेन की बात करता दिख रहा है। दावा है कि बंटवारे के लिए 50 हजार रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसमें 25 हजार रुपए पटवारी के हिस्से के थे। वीडियो में एक व्यक्ति नोटों की गड्डी देता दिख रहा है और पटवारी कहता है कि इतनी रकम से काम नहीं चलेगा।

निलंबन में कोटा रहेगा मुख्यालय

निलंबन अवधि में पटवारी का मुख्यालय एसडीएम कोटा कार्यालय में रहेगा और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा। कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को 7 दिन में आरोप पत्र तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अंतिम निष्कर्ष विभागीय जांच के बाद आएगा।

चक्रवात अर्नब पर अमित शाह का एक्शन, सीएम से फोन पर ली हालात की जानकारी, केंद्रीय टीम करेगी नुकसान का आकलन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के प्रभाव से हो रही बारिश के बीच केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्यों की मदद के लिए कदम बढ़ाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से फोन पर चर्चा कर हालात की जानकारी ली और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया। गृह मंत्रालय ने बताया कि नुकसान के आकलन के लिए जल्द ही अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमें (आईएमसीटी) भेजी जाएंगी। अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के साथ आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। उन्होंने एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत-बचाव में लगी हैं। अर्नब का असर छत्तीसगढ़ के दक्षिण और मध्य क्षेत्र में दिख रहा है। 28 अक्टूबर से बस्तर संभाग में बारिश और तेज हवा चल रही है, वहीं 29 अक्टूबर को रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा में भी बारिश हुई। कुछ निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है। आईएमसीटी टीमें प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान और मदद की जरूरतों का आकलन करेंगी, जिसके आधार पर आगे सहायता तय होगी। टीमों के पहुंचने की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।इससे पहले राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने भी राहत शिविरों, बचाव दलों और संसाधनों की तैयारी की समीक्षा की थी। मौसम विभाग के अनुसार सिस्टम धीरे-धीरे कमजोर होगा, लेकिन सावधानी जरूरी है।

राजधानी में पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 29 पुलिसकर्मियों की बदली तैनाती

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। कमिश्नरेट में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। जारी आदेश के तहत 29 अधिकारियों और कर्मचारियों की पदस्थापना बदली गई है। इसमें उपनिरीक्षक, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक स्तर के पुलिसकर्मी शामिल हैं। सभी को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से नई जगह तैनात किया गया है। खमतराई, डीडी नगर, सिविल लाइन, आमानाका, खम्हारडीह, सरस्वती नगर, गुढ़ियारी, कोतवाली, टिकरापारा, तेलीबांधा, गंज, कबीर नगर, राजेंद्र नगर के साथ महिला थाना, यातायात, कंट्रोल रूम और रक्षित केंद्र में बदलाव किए गए हैं।

महिला थाना और पिंक गश्त में बदलाव

खमतराई थाने की ज्योति राजपूत को महिला थाना, डीडी नगर के एएसआई राधेलाल साहू को रक्षित केंद्र, पिंक गश्त की स्वलेहा शेख को आमानाका और आमानाका की सरिता यादव को पिंक गश्त में भेजा गया है। रक्षित केंद्र के नागेंद्र सिंह को खमतराई, सरस्वती नगर के ऑसकर केरकेट्टा को रक्षित केंद्र और खम्हारडीह के अभय गणोरकर को यातायात में पदस्थ किया गया है।

कोतवाली, सिविल लाइन में नई तैनाती

गुढ़ियारी के सियाराम धुर्वे को रामनगर चौकी, कोतवाली की प्रीति वर्मा को महिला थाना, एसीपी कोतवाली कार्यालय के मेहत्तर सिंह को खम्हारडीह, सिविल लाइन के खेमराज वर्मा को एसीपी सिविल लाइन कार्यालय, महिला थाने की प्रमीला कुंजाम को कोतवाली भेजा गया है। कामता जांगड़े का डीडी नगर तबादला निरस्त कर महिला थाने में ही रखा गया है।

टिकरापारा, तेलीबांधा में फेरबदल

रक्षित केंद्र की लेखा अग्रवाल को सिविल लाइन, सिविल लाइन की चंद्रकला साहू को टिकरापारा, टिकरापारा के रामनारायण पटेल को तेलीबांधा भेजा गया। दानेश्वर वर्मा और एकेश्वर वर्मा को डीडी नगर, प्रमोद चंदेल को राजेंद्र नगर और सरस्वती सिन्हा को कंट्रोल रूम भेजा गया है।

रक्षित केंद्र से थानों में भेजे गए

बबीता बांधे को तेलीबांधा, विकास तिवारी को गंज, डिगेश्वरी ध्रुव को महिला थाना, अजय लकड़ा को यातायात, कमलेश दीवान को रक्षित केंद्र, अनिता द्विवेदी को टिकरापारा, प्रशांत साहू को कबीर नगर, डोमार देव को आमानाका और तुकेश्वर सिन्हा को कमल विहार सहायता केंद्र भेजा गया है।

जनजातीय अंचलों में पर्यटन से खुलेंगे रोजगार के द्वार, होम-स्टे से आत्मनिर्भर बनेंगे आदिवासी परिवार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जनजातीय अंचलों में होम-स्टे और पर्यटन के जरिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। राज्य सरकार की नई उद्योग नीति और होम-स्टे नीति के तहत बस्तर, सरगुजा, जशपुर जैसे क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं और महिला समूहों को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर द्वारा 28 अक्टूबर को एक दिवसीय राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम और बस्तर के जनजातीय हितग्राहियों को शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और आईआईएम रायपुर ने तकनीकी सहयोग दिया।

संस्कृति और पर्यटन से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था

टीआरटीआई संचालक हिना अनिमेष नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक जीवनशैली और प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के लिए आकर्षण हैं। होम-स्टे से स्थानीय परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होंगे और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलेगी।

तीन सत्रों में दिया गया प्रशिक्षण

पहले सत्र में पर्यटन विभाग की डॉ. शुभदा चतुर्वेदी ने होम-स्टे नीति, पंजीयन प्रक्रिया, मानकों और अनुदान की जानकारी दी। दूसरे सत्र में आईआईएम रायपुर की तौशीफ आयशा अंसारी ने स्वच्छता, अतिथि सत्कार, रखरखाव और कम संसाधन से व्यवसाय शुरू करने के टिप्स दिए।

अर्नव का असर, दो दिनों से झमाझम बारिश, खेतों में खड़ी व कटी धान की फसल पानी में डूबी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर/बिहारपुर। जिले सहित चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में चक्रवात का असर देखने को मिल रहा है। पिछले दो दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के कारण क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में काटकर रखी गई धान की फसल पानी में भीग गई है, जबकि तेज हवाओं के कारण खड़ी धान की फसल भी जमीन पर गिर गई है। इससे किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा होने की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग द्वारा पहले ही खराब मौसम को लेकर अलर्ट जारी किए जाने की जानकारी सामने आई थी। चक्रवात अर्नव के प्रभाव से सूरजपुर जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश, जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई गई थी। क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते कई खेतों में पानी भर गया है और नदी-नालों का जलस्तर भी बढ़ गया है। चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में धान की कटाई का कार्य शुरू हो चुका था। कई किसानों ने अपनी फसल काटकर खेतों में ही रखी थी, लेकिन अचानक शुरू हुई लगातार बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में पानी भर जाने से काटकर रखी गई धान की फसल भीग गई है। वहीं, कई किसानों की पकी हुई धान की फसल अभी भी खेतों में खड़ी है, जो तेज हवाओं के कारण जमीन पर गिर गई है। बारिश के पानी में धान की फसल डूबने से अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होने तथा धान के सड़ने और अंकुरित होने की आशंका बढ़ गई है। क्षेत्र के सैकड़ों किसान इस बेमौसम बारिश से प्रभावित हुए हैं। किसानों को चिंता है कि यदि जल्द मौसम साफ नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है। बारिश से धान की फसल को हुए नुकसान को लेकर क्षेत्र के किसानों ने कलेक्टर श्रीमती रेना जमील से तत्काल संज्ञान लेने की मांग की है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कड़ी मेहनत और लागत लगाकर धान की खेती की थी, लेकिन फसल पककर तैयार होने और कटाई के समय हुई लगातार बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है।

प्रभावित किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के सभी प्रभावित गांवों में राजस्व एवं कृषि विभाग की संयुक्त टीम भेजकर फसल नुकसान का तत्काल सर्वे कराया जाए। साथ ही जिन किसानों की धान की फसल बारिश और जलभराव के कारण खराब हुई है, उन्हें नुकसान के आकलन के आधार पर उचित क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाए। किसानों का कहना है कि कई परिवारों की आजीविका पूरी तरह खेती पर निर्भर है। ऐसे में धान की फसल को हुए नुकसान से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।

लगातार बारिश के कारण चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई स्थानों पर नदी-नाले उफान पर हैं। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण क्षेत्र में ठंडक भी बढ़ गई है। मौसम में आए अचानक बदलाव से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं, किसानों की निगाहें अब मौसम पर टिकी हुई हैं। किसान बारिश थमने और धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि खेतों में पड़ी धान की फसल को बचाया जा सके।

किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान

बगैर पंजीयन संचालन पर गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सील

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले में शैक्षणिक संस्थानों के संचालन में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करने तथा विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के निर्देशन में ग्राम तिलसिवां स्थित गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को बिना पंजीयन संचालित पाए जाने पर सील कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में अध्ययनरत डी.एम.एल.टी. एवं बी.एम.एल.टी. पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा से वंचित किए जाने तथा उनका शैक्षणिक वर्ष प्रभावित होने संबंधी शिकायत जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि संबंधित संस्थान का छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल, रायपुर में पंजीयन नहीं था। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. प्रशांत सिंह, तहसीलदार सूर्यकांत साय तथा नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश श्रेष्ठ एवं उनकी टीम की उपस्थिति में गुरुकुल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट को सील करने की कार्रवाई की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि जिले में संचालित अन्य संबंधित संस्थानों की भी जांच की जाएगी। जांच के दौरान पंजीयन, मान्यता एवं निर्धारित मापदंडों के पालन की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। किसी भी संस्थान में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

10वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्रों को विधायक ने दिया 25-25 हजार का चेक व प्रशस्ति पत्र

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की पहल के तहत 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। बुधवार को विधायक भूलन सिंह मरावी ने विद्यार्थियों को चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। विधायक भूलन सिंह ने प्रेमनगर में दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी। इसी घोषणा के तहत प्रेमनगर विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। शा. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटेया के कक्षा बारहवीं के छात्र प्रवीण सिरदार ने 91.40 प्रतिशत, दसवीं में के छात्र गुलशन ने 93.10 प्रतिशत, कु. आसमा ने 90.30 प्रतिशत तथा कु. डिंकल सिरदार ने 90.30 प्रतिशत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदननगर की कु. दीपा राजवाड़े ने 95.50 प्रतिशत, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रेमनगर की कु. ममता रानी ने 94.50 प्रतिशत तथा कु. प्रीति साहू ने 93 प्रतिशत, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवापारा कला की कु. प्रीति साहू ने 93.50 प्रतिशत एवं कु. प्रतिज्ञा दास ने 91.10 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन विद्यार्थियों को विधायक भूलन सिंह ने 25-25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि के चेक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र गुप्ता

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

प्रतापपुर। वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता महेंद्र गुप्ता का बुधवार को निधन हो गया। वे कुछ दिनों से अस्वस्थ थे जिनका वाराणसी के अस्पताल मे उपचार चल रहा था। जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। वे मनीष गुप्ता व विवेक गुप्ता के पिताश्री थे। उनके निधन की खबर से पत्रकार जगत, सामाजिक संगठनों और क्षेत्र के लोगों में शोक व्याप्त हो गया। वे पत्रकारिता और सामाजिक गतिविधियों से जुड़े रहे। उनके जाने से परिवार सहित परिचितों और शुभचिंतकों में शोक का माहौल है। दिवंगत महेंद्र गुप्ता का अंतिम संस्कार गुरुवार को प्रात: वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर किया गया। उनके निधन पर क्षेत्र के लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।

राशनकार्डधारियों के लिए ई-केवाइसी कराने की आज अंतिम तिथि

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जिले में प्रचलित राशनकार्डों के सभी पंजीकृत सदस्यों का ई-केवाइसी सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में वर्तमान में शेष बचे 27,339 सदस्यों का सत्यापन करने के लिए आज 30 अक्टूबर की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि राशनकार्ड में दर्ज सभी शेष सदस्य अपने नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान में जाकर ई-पॉस मशीन अथवा फेस ई-केवाइसी के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन तुरंत पूर्ण करा सकते हैं। प्रशासन द्वारा बचे हुए सदस्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान यदि कोई सदस्य अपने निवास स्थान पर नहीं पाया जाता है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो स्थानीय निकाय के माध्यम से उसका नाम राशनकार्ड से निरस्त करने की त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश स्थानीय निकायों को जारी किया गया है। ऐसे हितग्राही जो विशेष पिछड़ी जनजाति में आते हैं, दिव्यांग या अत्यधिक बुजुर्ग हैं और किसी कारणवश ई-केवाइसी पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उनके लिए प्रशासन द्वारा ऐसे सदस्यों की एक पृथक सूची उनके आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार कर स्थानीय निकाय में जमा कराई जा रही है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। खाद्य विभाग ने जिले के सभी राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की असुविधा या राशन बंद होने की स्थिति से बचने के लिए तय तिथि तक अपने नजदीकी राशन दुकान पर जाकर अपना ई-केवाइसी अनिवार्य रूप से पूरा करवा लें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या न हो।

किसानों से हमाली कराकर भुगतान करना भूल गए जिम्मेदार

दवनकरा धान खरीदी केंद्र का मामला, बढ़ा आक्रोश, सड़क पर उतरने की चेतावनी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत दवनकरा धान उपार्जन केंद्र में हमाली भुगतान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। धान की तौल, सिलाई और स्टेकिंग जैसे कार्य करने के बावजूद मेहनताना नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। किसानों ने 27 अक्टूबर को सामूहिक बयान जारी कर वर्ष 2025-26 सहित पूर्व वर्षों की बकाया राशि का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है। भुगतान में देरी को लेकर अब किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपनाने की चेतावनी भी दी है। किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधन की ओर से हमाली की राशि बैंक खातों में जमा कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में किसानों के सामने सवाल खड़ा हो गया है कि जब काम पूरा कराया गया, तो मेहनताने की राशि अब तक क्यों लंबित है। किसानों का कहना है कि हमाली भुगतान को लेकर लगातार मांग उठाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं निकल पाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से भुगतान के अभिलेखों की जांच कराने, पात्र किसानों की सूची तैयार करने और यह स्पष्ट करने की मांग की है कि किसका कितना भुगतान लंबित है तथा राशि जारी होने में देरी क्यों हो रही है।किसानों ने मांग की है कि वर्ष 2025-26 के साथ पूर्व वर्षों की लंबित हमाली राशि का भी परीक्षण कर पात्र हितग्राहियों के बैंक खातों में भुगतान कराया जाए। उनका कहना है कि मेहनताने के लिए बार-बार गुहार लगाना किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। दवनकरा धान खरीदी केंद्र में हमाली भुगतान का मुद्दा अब आंदोलन की चेतावनी तक पहुंच गया है। किसानों ने साफ कहा है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई और बकाया राशि का भुगतान नहीं कराया गया, तो वे सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

आदिवासी की जमीन शिक्षक के नाम पर दर्ज, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नही होने से रोष

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। बिहारपुर तहसील के ग्राम महुली में आदिवासी व्यक्ति के नाम दर्ज रही जमीन एक सरकारी शिक्षक के नाम पर दर्ज होने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शिकायत किए जाने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं से राजस्व विभाग की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे है।

प्राप्त शिकायत आवेदन के अनुसार, ग्राम महुली, पटवारी हल्का क्रमांक 07, राजस्व निरीक्षक मंडल बिहारपुर की खसरा संख्या 44 और 250 की कुल 0.43 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2000-01 के राजस्व अभिलेखों में मटुकलाल पिता जगत खैरवार के नाम दर्ज थी।शिकायतकर्ता मदनलाल जायसवाल ने आरोप लगाया है कि वर्तमान में उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों में शासकीय शिक्षक पवन कुमार जायसवाल के नाम दर्ज है। शिकायतकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भैयाथान के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में आरोप लगाया है कि आदिवासी व्यक्ति की जमीन गैर-आदिवासी के नाम दर्ज किए जाने के मामले की विधिवत जांच होनी चाहिए। आवेदन में यह भी दावा किया गया है कि नामांतरण के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए जाने की जानकारी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में संबंधित भूमि के अंतरण और नामांतरण से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी है, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित भूमि के आधार पर धान विक्रय तथा वर्ष 2025-26 में रोजगार गारंटी योजना के तहत डबरी निर्माण कार्य का लाभ लिया गया।

बिहारपुर का मामला,पटवारी की भूमिका पर सवाल

पटवारी की भूमिका पर सवाल

आवेदन में संबंधित हल्का पटवारी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया गया है कि भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और आवश्यक जानकारी सक्षम राजस्व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने संबंधित पटवारी के विरुद्ध भी जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि शिकायतकर्ता ने भूमि के नामांतरण की जांच कराने, खसरा संख्या 44 एवं 250 के वर्तमान अभिलेखों की वैधानिकता परखने और यदि नामांतरण अवैध पाया जाए तो भूमि को पुन: मूल खातेदार के नाम दर्ज करने की मांग की है।

जिला रेडक्रॉस अधिकारी नियुक्त किये गए शोमनाथ, अंतरराष्ट्रीय रेफरी बेग और सुरविंद बने सहायक अधिकारी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। जरूरतमंदों को रक्त के लिए भटकना न पड़े और आपदा की घड़ी में पीड़ित परिवारों को सहारा मिल सके, यही रेडक्रॉस की सेवा भावना का मूल उद्देश्य है। इसी सोच के साथ जिले में रेडक्रॉस सोसाइटी की गतिविधियों को मजबूत बनाने की पहल की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य शाखा, रायपुर ने जिला इकाई के कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए तीन अधिकारियों की नियुक्ति की है। राज्य शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला शाखा से प्राप्त प्रस्ताव तथा चेयरमैन बाबूलाल अग्रवाल की अनुशंसा पर नियुक्तियां की गई हैं। इससे जिले में स्वास्थ्य जागरूकता, रक्तदान, प्राथमिक उपचार और जरूरतमंदों की सहायता से जुड़े सेवा कार्यों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की उम्मीद है। आदेश के अनुसार, माध्यमिक शाला नरेशपुर में पदस्थ वरिष्ठ शिक्षक शोमनाथ चौबे को जिला रेडक्रॉस अधिकारी बनाया गया है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल रेफरी, पूर्व खेल अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ शासन के वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से सम्मानित पीटीआई शिक्षक मो. गौस बेग को सहायक जिला रेडक्रॉस अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा हाई स्कूल लांची के शिक्षक सुरविंद कुमार गुर्जर को भी सहायक अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। तीनों अधिकारियों को अपने मौजूदा शासकीय कार्यों के साथ रेडक्रॉस की जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। आदेश में कलेक्टर रेडक्रॉस कार्यालय में प्रतिदिन उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे संगठन के कामकाज में नियमितता और बेहतर समन्वय बना रहे। जिला स्तर पर व्यवस्था मजबूत होने से जरूरतमंदों को लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। नई नियुक्तियों से प्रशासनिक कामकाज को गति देने के साथ स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता, आपातकालीन सहायता और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से संचालित करने में मदद मिलेगी। राज्य शाखा का यह निर्णय सूरजपुर में रेडक्रॉस की जिला इकाई को सक्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

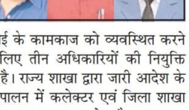

छग प्रदेश तृतीय वर्ग शा. कर्मचारी संघ ने भोजन अवकाश में सौपा स्मरण पत्र

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। लंबित मांगो को लेकर छग प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा भोजन अवकाश में जिला प्रशासन को स्मरण ज्ञापन सौंपा गया। मोदी की गारंटी के नाम से कर्मचारियों के लिए की गई घोषणा को लागू करने प्रदेश के सभी तहसील एवं जिला मुख्यालय में कलेक्टर एवं एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम पूर्व में संघ द्वारा ध्यानाकर्षण ज्ञापन 10 जून को दिया गया था तथा 07 से 11 जुलाई तक प्रदेश के जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया था और 30 सितंबर को प्रदेश के पांचो संभागीय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन रैली आयोजित कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था, किंतु संघ के ज्ञापनों पर निर्णय नहीं लिए जाने के कारण प्रदेश के कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है फल स्वरुप आज 29 अक्टूबर को निम्न बिंदुओं पर कर्मचारी हित में स्मरण ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें केंद्र के समान कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है किंतु प्रदेश के कर्मचारियों को उक्त लाभ से वंचित रखा गया है, राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों को केंद्रीय कर्मचारियों की भाँति देती थी महंगाई भत्ता तथा पेंशनरों को महंगाई राहत दिया जावे एवं डी ए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित की जाये। केंद्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 240 दिन के स्थान पर 300 दिनों का अवकाश नगदी कारण आदेश जारी किया जाए, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक का वेतनमान पुर्ननिरीक्षण किया जाए, प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए शिक्षक एलबी संवर्ग को समस्त सेवा का लाभ दिया जाए, शिक्षक पात्रता टीईटी के स्थान पर सीमित विभागीय परीक्षा का प्रावधान किया जाए, प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति की 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के सभी पदों पर अनुकंपा नियुक्ति, संविदा दैनिक वेतन भोगी, अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित करने तथा मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को भोजन अवकाश के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।

इस दौरान मनीष दीपक साहू जिला अध्यक्ष, महेश राम पैकरा जिला महा सचिव, निर्मल भट्टाचार्य प्रदेश उपाध्यक्ष छग हेड मास्टर फेडरेशन, अमरनाथ चौबे जिला उपाध्यक्ष, अनुरंजन देव जिला उपाध्यक्ष, आदित्य शर्मा जिला महामंत्री उपस्थित रहे।

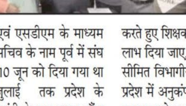

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/ प.ह.न.	भूमि का विवरण		धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
			खसरा क्रमांक	रकबा (हे.मे.)		
1	2	3	4	5	6	7
सरगुजा	लुण्ड्रा	मसगा/5	7/14	0.004	कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर	रघुनाथपुर, लुण्ड्रा, धौरपुर मार्ग (पार्ट-2) लंबाई कि.मी. 27 से 41 कुल 15 कि.मी. सड़क निर्माण हेतु।
			15/2	0.003		
			7/2	0.022		
			153	0.018		
			15/1	0.003		

कुल खसरा क्रमांक 05 कुल रकबा 0.050 हेक्टेयर

कार्यपालन अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग अम्बिकापुर

जी-262704241/1

मूक-बधिर महिला से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। थाना तुमला क्षेत्र में 37 वर्षीय दिव्यांग (मूक-बधिर) महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

क्या है मामला

26 अक्टूबर को पीड़िता के 34 वर्षीय भाई ने थाना तुमला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 25 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे वह शौच के लिए जा रहा था, तभी भदरा झाड़ी की तरफ से चिल्लाने की आवाज सुनकर वह दौड़ा। वहां उसने गांव के ही युवक चंद्रहास कुमार (20 वर्ष) को अपनी दिव्यांग बहन के साथ दुष्कर्म करते देखा। भाई को देखकर आरोपी कपड़े, पर्स और मोबाइल मौके पर छोड़कर भाग गया। रिपोर्ट पर थाना तुमला में अपराध क्रमांक 59/2026, धारा 64(1), 64(2)(i) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

तत्काल गिरफ्तारी और मेडिकल

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और पीड़िता का विधिवत मेडिकल परीक्षण कराया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी चंद्रहास कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी पीएसआई जितेंद्र कुमार साहू, पीएसआई विमलेश्वरी मरकाम, प्रधान आरक्षक फ्रांसिस बेक और आरक्षक मुकेश भगत की अहम भूमिका रही।

डीआईजी एवं एसएसपी जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर पुलिस पूरी तरह संवेदनशील है। दिव्यांग महिला से जुड़े इस गंभीर मामले में तत्काल कार्रवाई की गई है और आरोपी के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

जशपुर में सुरक्षित बचपन अभियान तेज, तीन स्कूलों में विधिक जागरूकता शिविर, बच्चों को पॉक्सो एक्ट और साइबर सुरक्षा की दी जानकारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिले में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे सुरक्षित बचपन अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर ने बड़ी पहल की है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में 28 अक्टूबर को शहर के तीन प्रतिष्ठित स्कूलों में एक साथ जागरूकता शिविर का सफल आयोजन किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलिंटियर्स के सहयोग से यह शिविर देव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल जशपुर, सेंट जेवियर इंग्लिश मीडियम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शांति भवन जशपुर और स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम नवीन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जशपुर में आयोजित हुआ।

कौन-कौन रहे मौजूद

शिविर को खास बनाने के लिए स्वयं न्यायाधीशों ने स्कूलों में पहुंचकर बच्चों से सीधा संवाद किया।

- **देव पब्लिक स्कूल**: यहां जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) जनार्दन खरे एवं जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी जनार्दन खरे उपस्थित रहे।
- **सेंट जेवियर स्कूल**: यहां व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी सुश्री दिव्या गोयल ने बच्चों को कानून की बारीकियां समझाईं।
- **स्वामी आत्मानंद स्कूल**: यहां प्रशिक्षु न्यायाधीश अभिनव कुमार अग्रवाल ने छात्रों को जागरूक किया।

बच्चों को क्या सिखाया गया

शिविर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपने अधिकारों और खतरों के प्रति सजग बनाना था।

- पॉक्सो एक्ट 2012: बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और उसके लिए कड़े दंड के प्रावधानों के बारे में बताया गया।
- गुड टच-बैड टच: बच्चों को सहज उदाहरणों से समझाया गया कि कौन सा स्पर्श सामान्य है और कौन सा असहज। असहज महसूस होने पर तुरंत मना करना और भरोसेमंद व्यक्ति को बताना सिखाया गया।
- साइबर सुरक्षा: मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और अनजान लोगों से चैटिंग के खतरों से अवगत कराया गया। अपनी निजी फोटो या जानकारी किसी से साझा न करने की सलाह दी गई।
- बाल अधिकार: शिक्षा का अधिकार, संरक्षण का अधिकार और हेल्पलाइन नंबरों - चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, पुलिस 112 और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की निशुल्क सहायता के बारे में जानकारी दी गई।

बच्चों ने भी सवाल-जवाब कर अपनी जिज्ञासाएं शांत की। शिक्षकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से बच्चे न केवल सुरक्षित रहेंगे, बल्कि भविष्य में जागरूक नागरिक भी बनेंगे।

कार्तिक मास में भक्ति में लीन हुए श्रद्धालु, पमशाला के राधा-कृष्ण मंदिर में भजन-कीर्तन जारी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कार्तिक मास के पावन अवसर पर ईब नदी तट स्थित प्रसिद्ध श्री राधा-कृष्ण मंदिर, पमशाला में भक्ति की बयार बह रही है। 27 अक्टूबर से शुरू हुआ मासिक भजन-कीर्तन कार्यक्रम 24 नवंबर तक चलेगा, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं।

सुबह-शाम हो रहा भजन-कीर्तन

मंदिर में प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे से भजन-कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। क्षेत्र की विभिन्न कीर्तन मंडलियां बारी-बारी से भजन, कीर्तन और राधा-कृष्ण के भक्तिमय गीतों की प्रस्तुति दे रही हैं। ढोलक-मंजीरे की थाप और भजनों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय बना हुआ है।

श्रद्धालुओं से शामिल होने की अपील

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी एवं अखिल भारतीय कंवर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कौशल्या साय ने क्षेत्र की सभी भजन मंडलियों और श्रद्धालुओं से इस आयोजन में शामिल होकर पुण्य लाभ लेने की अपील की है। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय कंवर समाज, पमशाला के तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। आयोजन को सफल बनाने में समाज के पदाधिकारी और स्थानीय श्रद्धालु जुटे हुए हैं।

हिंदू मान्यता में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस दौरान किए गए भजन-कीर्तन और साधना का विशेष फल मिलता है। ईब नदी तट के सुरम्य वातावरण में स्थित यह मंदिर कार्तिक मास में श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

नए तहसील भवन के लिए 1.25 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति, राजस्व कार्यों में आएगी तेजी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। जिले के तपकरा क्षेत्रवासियों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन ने तपकरा में नवीन तहसील कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ 25 लाख 2 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नए तहसील कार्यालय भवन के निर्माण से क्षेत्र में राजस्व संबंधी कार्यों के संचालन में सुविधा होगी। यह भवन प्रशासनिक सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

तपकरा जशपुर जिले की एक महत्वपूर्ण तहसील है, जहां बड़ी संख्या में आदिवासी ग्रामीण आबादी निवास करती है। यहां वर्तमान में तहसील कार्यालय छोटे और पुराने भवन में संचालित हो रहा था, जिससे आम लोगों को बैठने, दस्तावेजों के रखरखाव और सुनवाई में काफी परेशानी होती थी।

नए भवन से राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण जैसे- नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, खसरा-नक्शा सुधार जैसे हजारों लंबित मामलों का निपटारा तेज होगा। नए भवन में आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनेगा। किसानों और ग्रामीणों को जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, ऋण पुस्तिका जैसे कार्यों के लिए बेहतर कार्यालयीन सुविधाएं, प्रतीक्षा कक्ष और व्यवस्थित काउंटर मिलेंगे। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व अमले के लिए पर्याप्त कक्ष होने से कामकाज में पारदर्शिता और गति आएगी।

प्रशासकीय स्वीकृति मिलने के बाद अब लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर प्रक्रिया शुरू कर जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। क्षेत्र के लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जशपुर के 37 यात्री करेंगे अमृतसर, स्वर्ण मंदिर और वैष्णोदेवी के दर्शन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत जशपुर जिले के 37 सौभाग्यशाली यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा। नवंबर माह के लिए तीर्थ स्थल का निर्धारण कर दिया गया है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इस बार यात्रियों को अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर, माता वैष्णो देवी मंदिर और वाघा बॉर्डर का दर्शन कराया जाएगा। यात्रा की अवधि 10 से 15 नवंबर तक रहेगी।

यात्रा के लिए इच्छुक पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी की छायाप्रति और मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

कौन कर सकता है आवेदन

छत्तीसगढ़ के निवासी वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक), विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं। आवेदक ने पहले इस योजना का लाभ न लिया हो।आवेदक शासकीय सेवक न हो और किसी गंभीर संक्रामक रोग से ग्रसित न हो। एपीएल हितग्राही आयकरदाता न हो।

चयन का मापदंड

ग्रामीण क्षेत्र से 75% और शहरी क्षेत्र से 25% यात्रियों का चयन। बीपीएल परिवार से 80% और एपीएल से 20% यात्री। 65 वर्ष से अधिक उम्र के अकेले यात्रा करने में असमर्थ व्यक्ति 21 से 50 वर्ष का एक सहायक ले जा सकते हैं। पति-पत्नी में से एक का चयन होने पर जीवनसाथी भी साथ जा सकेगा। इच्छुक व्यक्ति अपने विकासखंड के जनपद पंचायत या नगर पालिका और जिला स्तर पर समाज कल्याण विभाग में आवेदन जमा कर सकते हैं।

कुनकुरी को मिली बड़ी सौगात, एसडीएम कार्यालय भवन के लिए 1 करोड़ 25 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति, जल्द शुरू होगा निर्माण

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने जशपुर जिले के कुनकुरी अंचल को बड़ी सौगात दी है। कुनकुरी में नवीन अनुविभागीय कार्यालय (राजस्व) भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ 25 लाख 2 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार कुनकुरी अनुविभाग जशपुर जिले का सबसे बड़ा और व्यस्त अनुविभाग है। यहां कुनकुरी और दुलदुला तहसील के सैकड़ों गांवों के लोग प्रतिदिन अपने राजस्व और प्रशासनिक कार्यों के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अब तक अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पुराने, जर्जर और कम जगह वाले भवन में संचालित हो रहा था। इससे न केवल अधिकारियों-कर्मचारियों को काम करने में परेशानी होती थी, बल्कि आम जनता को भी घंटों इंतजार करना पड़ता था।

नए भवन से क्या-क्या बदलेगा

राजस्व मामलों में तेजी: नामांतरण, खाता विभाजन, बटांकन, सीमांकन, त्रुटि सुधार जैसे राजस्व प्रकरणों का निराकरण अब तेज गति से हो सकेगा। नए भवन में रिकॉर्ड रूम और सुनवाई कक्ष की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

आम जनता को सुविधा: जाति प्रमाण पत्र, निवास, आय, ऋण पुस्तिका, भू-अर्जन से जुड़े मामलों के लिए लोगों को एक ही परिसर में व्यवस्थित काउंटर मिलेंगे। बैठने और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण: कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, चुनाव और अन्य शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुविभाग स्तर पर बेहतर समन्वय और बैठक व्यवस्था बन सकेगी।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया है। लोगों का कहना है कि कुनकुरी के तेजी से बढ़ते शहरीकरण और प्रशासनिक बोझ को देखते हुए नए भवन की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जो अब पूरी हुई है। लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

आरबीसी 6-4 के तहत 7 मृतकों के परिजनों को 28 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत, कलेक्टर ने दिए शीघ्र भुगतान के निर्देश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर कार्यालय जशपुर द्वारा जिले में प्राकृतिक आपदा और दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 7 लोगों के परिजनों के लिए बड़ी राहत दी गई है। छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 (आरबीसी 6-4) के तहत कुल 28 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के तहसील फरसाबहार, पत्थलगांव, सन्ना और कुनकुरी क्षेत्र में नदी, बांध, डेम, तालाब और खेत की डबरी में डूबने तथा सर्पदंश से 7 लोगों की मृत्यु हुई थी। इन सभी प्रकरणों में जांच के बाद प्रत्येक मृतक के निकटतम वारिस को 4-4 लाख रुपये के मान से सहायता स्वीकृत की गई है।

इन परिवारों को मिलेगी सहायता

खारी बहार निवासी स्व. कृपा सागर कुजूर, राजाआमा निवासी स्व. जलसिंह सिदार, कामारिमा निवासी स्व. कृष्णा राम विश्वकर्मा, पकरीकछार निवासी स्व. राजेन्द्र कुंवरघट, मुंडा निवासी स्व. शाखा, पतिचराई खारा निवासी स्व. फुलकुमारी बाई, मुंडाडीह निवासी स्व. पिंकेश्वर साय।

कलेक्टर रोहित व्यास ने सभी संबंधित तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत राशि का भुगतान हितग्राहियों के बैंक खाते में शीघ्र किया जाए, ताकि संकट की इस घड़ी में परिवारों को आर्थिक संबल मिल सके।

गुड टच और बैड टच का फर्क समझाने स्कूलों में पहुंचे जज बच्चों को किया साइबर खतरों से अलर्ट

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुर। बच्चों को यौन अपराधों और तकनीकी दुनिया के खतरों से महफूज रखने के लिए जशपुर में 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत बड़ी पहल की गई है। अदालतों में सुनवाई करने वाले जजों ने खुद स्कूलों में पहुंचकर छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया और उन्हें पॉक्सो एक्ट से लेकर 'गुड टच-बैड टच' जैसे संवेदनशील लेकिन बेहद जरूरी विषयों की जानकारी दी। यह पूरा जागरूकता कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जशपुर) के मार्गदर्शन में 28 अक्टूबर को संचालित किया गया।

तीन प्रमुख स्कूलों में लगा विशेष शिविर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जशपुर के पैरालीगल वॉलिंटियर्स के माध्यम से जिले के तीन अलग-अलग विद्यालयों में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। इनमें शहर के देव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल, सेंट जेवियर इंग्लिश मीडियम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (शांतिभवन) और स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम नवीन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल रहे।

न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों से किया संवाद

इन तीनों स्कूलों में आयोजित शिविरों में अलग-अलग न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। देव पब्लिक स्कूल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) जनार्दन खरे और जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सरोजनी जनार्दन खरे ने बच्चों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। इसी तरह, सेंट जेवियर स्कूल में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी दिव्या गोयल मौजूद रहीं, जबकि स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रशिक्षु न्यायाधीश अभिनव कुमार अग्रवाल ने उपस्थित रहकर बच्चों से संवाद स्थापित किया।

पॉक्सो और बाल अधिकारों पर फोकस

शिविर के दौरान बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हर अहम पहलू पर चर्चा की गई। न्यायिक अधिकारियों ने बच्चों को विशेष रूप से पॉक्सो एक्ट और गुड टच-बैड टच की पहचान करना सिखाया। इसके साथ ही, बाल अधिकार एवं संरक्षण, तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के तरीके (साइबर सुरक्षा) और एक सुरक्षित बचपन के महत्व के बारे में विस्तार से अलर्ट करते हुए उन्हें जागरूक किया गया।

सूरजपुर हत्याकांड के दोषियों को फांसी देने खुद जल्लाद बनने को तैयार पुलिस नेता दीवान, सीएम को लिखा- मुफ्त में करूंगा काम

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

क्या है पूरा मामला?

14 अक्टूबर 2024 को सूरजपुर में एक हेड कॉन्स्टेबल की पत्नी के साथ दुष्कर्म के बाद मां और उसकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले में स्पेशल कोर्ट ने 3 दोषियों - कुलदीप, चंद्रकांत और रिंकू को फांसी की सजा और चौथे आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित सूरजपुर मां-बेटी हत्याकांड के दोषियों को फांसी देने के लिए अब खुद जल्लाद बनने की पेशकश सामने आई है। संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्ज्वल दीवान ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और गृहमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वे बिना एक रुपया लिए जल्लाद बनने को तैयार हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा - "रेप-मर्डर के दोषियों कुलदीप साहू, चंद्रकांत चौधरी और रिंकू विश्वकर्मा को फांसी पर मैं चढ़ाऊंगा।"

उज्ज्वल दीवान ने पत्र में क्या लिखा?

दीवान ने पत्र में लिखा है कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब फांसी दी जाए तो सक्षम अधिकारियों की निगरानी में वे यह काम मुफ्त में करेंगे। इसका मकसद पुलिस परिवार के साथ खड़े रहना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों की सुरक्षा और सम्मान का मुद्दा गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

कौन हैं उज्ज्वल दीवान?

2010 में धमतरी पुलिस में आरक्षक के पद पर भर्ती हुए, बाद में इस्तीफा दे दिया। पुलिस कर्मचारियों के अधिकारों की आवाज उठाने पर उन पर राजद्रोह और पुलिस द्रोह के केस दर्ज होने का दावा करते हैं। उनके पिता हेड कॉन्स्टेबल पद से रिटायर हुए हैं। 2023 में आजाद जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। वर्तमान में संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं।

सुरक्षा में कटौती पर पीसीसी चीफ बोले- घटना हुई तो जिम्मेदार होगी सरकार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के भाजपा और कांग्रेस के 116 नेताओं की सुरक्षा श्रेणी में कटौती के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस फैसले पर गंभीर चिंता जताते हुए सरकार को चेतावनी दी है। बैज ने कहा, "प्रदेश में नक्सलवाद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा नक्सली अब भी सक्रिय हैं और कुछ दूसरे राज्यों में चले गए हैं।

हम भी चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो, लेकिन जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर सुरक्षा कम करने के बाद कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।" उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह अपने नेताओं को अतिरिक्त सुरक्षा दे रही है जबकि विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा घटा रही है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर व ऑफसेट पुराना पोस्ट ऑफिस रोड दरीपारा अंबिकापुर छ. ग. पिन नं. 497001 से मुद्रित व वार्ड क्र. 10 कुनकुरी जशपुर से प्रकाशित। संपादक - लक्ष्मण सिंह